

कमल संदेश

वर्ष-17, अंक-05

01-15 मार्च, 2022 (पाक्षिक)

₹20



'भाजपा राष्ट्रवाद, विकासवाद और गरीब-कल्याण के प्रति समर्पित पार्टी है'



भाजपा के 'संकल्प पत्र' लोक कल्याणकारी उपायों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
पर विशेष साक्षात्कार

उत्तर प्रदेश में भाजपा की
राजनीतिक यात्रा: एक नजर

राष्ट्रपति अभिभाषण पर
राज्यसभा में प्रधानमंत्री का वक्तव्य



रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश) में जनाभिवादन स्वीकार करते
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा



मौड़ मंडी (पंजाब) में एक जनसभा को संबोधित करते
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा



खीरी (उत्तर प्रदेश) में एक जनसभा के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते उत्तर प्रदेश भाजपा नेतागण



कोरांव (उत्तर प्रदेश) में जनाभिवादन स्वीकार करते
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह



औरैया (उत्तर प्रदेश) में एक विशाल रैली को संबोधित करते
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह



गोंडा (उत्तर प्रदेश) में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

संपादक

प्रभात झा

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सरी

सह संपादक

संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक

विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया

राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण

सतीश कुमार

इ-मेल

mail.kamalsandesh@gmail.com

mail@kamalsandesh.com

फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org



उत्तर प्रदेश की सुख, शांति और खुशहाली के लिए भारी बहुमत से भाजपा को विजयी बनाइये: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 फरवरी, 2022 को रिमाउंट डिपो मैदान, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे...



09 भाजपा राष्ट्रवाद, विकासवाद और गरीब-कल्याण के प्रति समर्पित पार्टी है : जेपी नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने वक्तव्य में उत्तर प्रदेश की...

12 योगी आदित्यनाथ सरकार ने वादों को जमीन पर उतारकर पूरा करने का काम किया है : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने जनता से...



13 समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 20 फरवरी, 2022 को प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को...



14 परिवार में कम से कम एक रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 8 फरवरी, 2022 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश...



वैचारिकी

सिद्धांत और नीतियां / पं. दीनदयाल उपाध्याय 23

श्रद्धांजलि

नहीं रहे गायक-संगीतकार बप्पी लाहिड़ी 25

साक्षात्कार

मोदी सरकार में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया : डॉ. भारतीबेन शियाल 28

लेख

उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक यात्रा: एक नजर / राम प्रसाद त्रिपाठी 30

'मुद्रा योजना' महिला नेतृत्व वाले विकास की गाथा लिखने में सहायक सिद्ध हो रही है / विकास आनन्द 32

अन्य

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव : दृष्टि पत्र 2022 16

गोवा विधानसभा चुनाव : संकल्प पत्र 2022 17

मणिपुर विधानसभा चुनाव : भाजपा का घोषणा पत्र 2022 18

पंजाब विधानसभा चुनाव : संकल्प पत्र 2022 19

देश में 2021-22 के दौरान 316.06 मिलियन टन रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ 20

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर 21

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का हुआ भुगतान 22

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में प्रधानमंत्री का जवाब 26



नरेन्द्र मोदी

हम सबने मां भारती का नमक खाया है, हिंदुस्तान का नमक खाया है। हम सबका परिश्रम देश के लिए होना चाहिए, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि गरीब के जीवन में मुश्किलें कम से कम हों।

जगत प्रकाश नड्डा

जिस प्रकार वर्ष 2017 में दिए आपके वोट के कारण उत्तर प्रदेश से गुंडाराज का खात्मा करने और सुशासन की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, उसी प्रकार वर्ष 2022 में पुनः भाजपा को वोट देकर यहां समर्थ, सक्षम और प्रगतिशील सरकार बना दीजिये।



अमित शाह

मोदीजी और योगीजी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इसलिए प्रदेश का गरीब, महिला, युवा और हर वर्ग भाजपा के साथ एकमुश्त खड़ा है।

राजनाथ सिंह

उत्तराखण्ड में जनता विकास और सुशासन के पक्ष में है। भाजपा सरकारों की विश्वसनीयता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के चलते प्रदेश की जनता पुनः भाजपा सरकार बनाने जा रही है।



बी.एल. संतोष

कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अपने 1704 छात्रावासों में रहने वाली ओबीसी छात्राओं के सशक्तिकरण, 'आत्मरक्षा' प्रशिक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। बहुत अच्छा बसवराज बोम्मई और कोटा श्रीनिवास पूजरी!

नितिन गडकरी

14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद सभी वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि एवं नमन। उनके बलिदान को देश नहीं भूलेगा।



“भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी अर्थात् Integrated है। टुकड़े-टुकड़े में विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से ठीक हो सकता है परंतु व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं। पश्चिम की समस्या का मुख्य कारण उनका जीवन के संबंध में टुकड़ों-टुकड़ों में विचार करना तथा फिर उन सबको थगली लगाकर जोड़ने का प्रयत्न है।

—दीनदयाल उपाध्याय



कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को

महाशिवरात्रि (01 मार्च)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

भाजपा देश की एकमात्र आशा

जै से-जैसे विधानसभा चुनाव एक चरण से दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं, प्रचार-प्रसार और भी अधिक गति पकड़ रहा है। अब जबकि गोवा, पंजाब एवं उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सबका ध्यान उत्तर प्रदेश और मणिपुर की ओर है। अब तक चुनावी जनसभाओं, रैलियों रोड-शो एवं मतदान में जिस प्रकार की भारी जन भागीदारी दिखी है, उससे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, सुंदरता एवं जीवंतता का अनुमान लगाया जा सकता है। जहां उत्तराखंड में 62 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया तथा गोवा में लगभग 80 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वहीं पंजाब में लगभग 72 प्रतिशत लोगों ने मत डाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं और विभिन्न चरणों में अब तक 60 प्रतिशत से भी अधिक मतदान हो चुका है। भाजपा की जनसभाओं, रैलियों एवं रोड-शो में अपार जनसमूह एवं अद्भुत उत्साह से यह स्पष्ट है कि जनता का रुझान किस ओर है। आज भाजपा स्पष्ट रूप से एक ऐसे राजनैतिक दल के रूप में उभरी हैं जो विकास, सुशासन, कर्मठ कार्यशैली, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं एवं युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता हेतु जानी जाती है।

परिणाम यह है कि आज भाजपा को समाज के हर वर्ग का व्यापक समर्थन एवं आशीर्वाद मिल रहा है।

चुनावों के दौरान भाजपा ने सभी चुनावी पांच राज्यों के लिए 'संकल्प पत्र' जारी किया है। इन संकल्प पत्रों में न केवल भाजपा की दृष्टि समाहित है, बल्कि इन प्रदेशों की जनाकांक्षाएं भी प्रतिबिंबित हुई हैं। ध्यान देने योग्य हैं कि इन 'संकल्प पत्रों' को तैयार करने में जनता की भागीदारी भी किसी-न-किसी रूप में सुनिश्चित की गई है। इन संकल्प पत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता भी झलकती है। इन संकल्प पत्रों में गरीब, किसान, मजदूर, महिला एवं युवा केंद्रित कई अभिनव योजनाएं हैं जो कि विभिन्न प्रदेशों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इनमें इन पांच प्रदेशों के विकास, सुशासन एवं प्रगति के बीज हैं जो इन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

भाजपा ने सभी चुनावी पांच राज्यों के लिए 'संकल्प पत्र' जारी किया है। इन संकल्प पत्रों में न केवल भाजपा की दृष्टि समाहित है, बल्कि इन प्रदेशों की जनाकांक्षाएं भी प्रतिबिंबित हुई हैं

सभी पांच राज्यों के 'संकल्प पत्र' लोक-कल्याणकारी योजनाओं को और भी अधिक सुदृढ़ करने के लिए कृत-संकल्पित हैं। एक ओर जहां 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के अंतर्गत किसानों को दी जा रही राशि के अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का संकल्प है वहीं दूसरी ओर इनमें अनेक अन्य अभिनव योजनाओं का भी समावेशित किया गया है। गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना का विस्तार देते हुए तीन निःशुल्क गैस सिलिंडर के साथ-साथ उनकी शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं पर भी विशेष बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सरदार बल्लभ भाई पटेल एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन, छह मेगा फूड पार्क, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुदृढ़ करने, गन्ना मिल के आधुनिकीकरण, उत्तराखंड में सहकारी दुग्ध उत्पादन,

पर्वतमाला परियोजना, मिशन हिमवंत, गोवा में कई योजनाओं के अलावा 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, मणिपुर में फोफो ट्रेन, लोकटक मेगा इको-टूरिज्म, पर्यटन के लिए स्टार्ट-अप तथा पंजाब के किसानों के लिए कर्ज माफी, स्थानीय युवाओं को नौकरियों में आरक्षण, आतंकवाद प्रभावित लोगों को सहायता राशि, 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, महिलाओं के

लिए आरक्षण जैसी दूरदर्शी योजनाएं शामिल हैं।

जहां भी भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिला है तथा जिन प्रदेशों में इसकी सरकारें बनी हैं वहां भाजपा ने भ्रष्टाचार-मुक्त कानून व्यवस्था, सुशासन एवं परफॉर्मेंस के नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड एवं मणिपुर में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि भाजपा सरकारों ने किस प्रकार इन प्रदेशों का कार्याकल्प कर विकास एवं सुशासन का पथ प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं दूरदर्शी नेतृत्व में भाजपा पूरे देश में जनाकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी पर जनविश्वास दिनोंदिन और अधिक मजबूत हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वंशवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी एवं संकीर्ण सोच रखने वाले राजनैतिक दलों के बीच आज भाजपा देश की एकमात्र आशा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org



संगठनात्मक गतिविधियां : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022

उत्तर प्रदेश की सुख, शांति और खुशहाली के लिए भारी बहुमत से भाजपा को विजयी बनाइये: नरेन्द्र मोदी

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सात चरणों में संपन्न होने हैं। अभी तक पहले चरण में 10 फरवरी को, दूसरे चरण में 14 फरवरी को और तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान संपन्न हुए हैं, जबकि चौथे चरण में 23 फरवरी को, पांचवें चरण में 27 फरवरी को, छठे चरण में 3 मार्च को और सातवें चरण में 7 मार्च को मतदान संपन्न होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने वक्तव्य में भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश को भयमुक्त, दंगामुक्त और अपराधमुक्त बनानेवाली भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने की अपील की

सहारनपुर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 फरवरी, 2022 को रिमाउंट डिपो मैदान, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे।

श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है कि जो उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, उसे वोट देंगे। जो उत्तर प्रदेश को दंगामुक्त रखेगा, उसे वोट देंगे। जो हमारी बहन-बेटियों को भयमुक्त रखेगा, उसे वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा, उसे वोट देंगे।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को 'पीएम आवास योजना' के घर मिलते रहें, इसके लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना का पैसा जाता रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी आज विश्व में अपना डंका बजा रही है। 2017 से पहले इस उद्योग की कोई सुध लेने वाला नहीं था। भाजपा सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' में शामिल करके इसे ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है, जबकि लकड़ी नक्काशी का काम तो पहले भी होता था, लेकिन इतनी सरकारें और इतने नेता आए, लेकिन किसी ने आपको पूछा ही नहीं।

आज नक्काशी का जो काम है, उसको जीआई टैग डबल इंजन की सरकार ने ही दिलाने का काम किया है।

कासगंज

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 फरवरी, 2022 को पटियाली, कासगंज (उत्तर प्रदेश) में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया।

श्री मोदी ने सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना पूरा जीवन अंत्योदय और गरीब कल्याण के लिए समर्पित किया, दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। जब मैं आज कासगंज आया हूँ तो बाबू जी की याद आना स्वाभाविक है। बाबू कल्याण सिंह जी का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा। उनका कासगंज से कितना साथ रहा, ये हम सब जानते हैं। उनकी प्रेरणा से भाजपा निरंतर गरीबों की, पिछड़ों की सेवा कर रही है।

उन्होंने कहा कि जहां डर होता है, जहां अपराध होता है। जहां माफियाराज होता है, फिरौती-छीना झपटी होती है, वहां विकास संभव नहीं होता। कानून व्यवस्था स्थापित करना कोई छोटी बात नहीं है। योगीजी ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का जो माहौल दिया है, उसने समृद्धि का नया द्वार खोला है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल आवश्यक है, वह माहौल योगीजी सरकार ने दिया है। दबंग, दंगा और माफियाराज को अब हमें उत्तर प्रदेश से हमेशा के लिए बाहर कर देना है।

कन्नौज

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 फरवरी, 2022 को अन्नपूर्णा मंदिर, कन्नौज (उत्तर प्रदेश) में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया।

श्री मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादियों की कुनीति का एक गवाह कन्नौज का इत्र उद्योग भी है। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार से, अपने काले कारनामों से यहां के इत्र कारोबार को बदनाम किया। इन्होंने इत्र को करप्शन से जोड़ा। हम इस इत्र को ग्लोबल ब्रांड बनाने में जुटे हैं। जो काम इन्हें छोटे लगते हैं, हमें उनमें गरीब की तरक्की का समाधान दिखता है। हमें उसकी चिंता थी जिसके पास या तो जमीन है ही नहीं, या फिर बहुत कम है। हमें उन बहनों की चिंता थी जिनके लिए पशुपालन आत्मनिर्भरता का, आत्मसम्मान का माध्यम है। सिर्फ विकास की बातें करने से विश्वास नहीं आता है, लेकिन जब नीयत साफ होती है, मेहनत दिन रात होती है, जनता के सुख-दुख की चिंता होती है, तभी सामान्य मानवीय के मन में विश्वास पैदा होता है। चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, हाईवे-एक्सप्रेसवे बनाने हो, गांव के पास ही अच्छे भंडार, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग लगाने हों— इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई हैं।

अकबरपुर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर (कानपुर देहात) के शहजादपुर स्थित मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया।

श्री मोदी ने कहा कि हमने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की। इससे उनके बैंक खाते में सीधे पैसा भेजना शुरू किया। हमने फसल बीमा के नियमों में बदलाव किया, उनके लिए विशेष पेंशन योजना शुरू की। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में पशुपालकों और मछली पालन करने वालों को लाभ दिया। माफियावादियों ने कानपुर के उद्योगों को तालाबंदी की तरफ धकेला, डबल इंजन सरकार कानपुर में मेगा लेदर पार्क बना रही है। जो पहले सरकारों में थे, उन्होंने देशी आयात को प्राथमिकता देकर जालौन के कागज उद्योग को भी बर्बाद कर दिया था। लेकिन योगीजी की सरकार ने कागज उद्योग के साथ-साथ जालौन के मटर को भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कदम उठाए। मुझे खुशी है कि हमने जो पैसा दिल्ली से भेजा उसकी पाई-पाई का उपयोग हुआ और उत्तर प्रदेश में 34 लाख घर पक्के घर गरीबों को बनाकर दिए गए।

सीतापुर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में सीतापुर (मिलिट्री ग्रास फार्म) में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया।

श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के होने का मतलब है दंगाराज, माफियाराज और गुंडाराज पर कंट्रोल। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा-पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का मतलब है बहन-बेटियों की मनचलों से सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का मतलब है— गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का मतलब है— केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम।

उन्होंने कहा कि सीतापुर के बुनकर भाइयों का परिश्रम दुनिया भर में दिखे, इसके लिए 'हम वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) लेकर आए हैं। देश के हर जिले में ऐसे उत्पाद हैं, उनके लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। वोकल फॉर लोकल अभियान से सीतापुर की दरी बिकने लगी, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मैं आपके लिए बोलता हूं। वे लोग यहां के कारीगरों के बजाय विदेश से खरीद लाते थे।

श्री मोदी ने कहा कि सीतापुर के किसान कभी नहीं भूल सकते कि कैसे गन्ना बेचने आए किसानों पर मिल के फाटक के सामने लाठियां बरसाई गई थीं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड चीनी मिलों को बंद करने का भी रहा है। योगी सरकार नई चीनी फैक्ट्रियां भी लगा रही हैं और पुरानी फैक्ट्रियों की क्षमता भी बढ़ा रही है। हम एथेनॉल पर जोर दे रहे हैं ताकि किसानों की आय बढ़े। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की सुख, शांति और खुशहाली के लिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइये।

फतेहपुर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के बहुआ रोड पर एफसीआई के पास मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया।

श्री मोदी ने कहा कि दशकों तक देश और उत्तर प्रदेश में घोर परिवारवादी सत्ता में आए, इन्होंने छोटे किसानों के लिए कुछ किया। किसानों के नाम पर झूठी घोषणाएं करके अपने रिश्तेदार और परिवारवादियों की तिजोरियां भरी हैं। बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो, आपका संकट दूर करने के लिए हम चिंता करते हैं। फतेहपुर के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं कि पिछली सरकार के लोग यहां कैसे कैसे दबंगई करते थे। सरकारी जमीनों पर कब्जा, अवैध खनन माफिया ने इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। योगीजी की

‘हम नवां पंजाब बनायेंगे जहां चारों ओर खुशहाली होगी’



सरकार ने इन माफिया का इलाज करके सही किया है।

श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 44 हजार करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से खेत-खेत तक पानी पहुंचाया। केन बेतवा लिंक परियोजना को मैं पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन परिवारवादियों को अगर मौका मिल गया तो ये उसमें भी रोड़ा अटकाएंगे। हमारी सरकार यहां 'हर घर जल' अभियान चला रही है। भाजपा सरकार का फतेहपुर और इस क्षेत्र से स्नेह है। घोर परिवारवादियों ने यहां से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन भाजपा ने फतेहपुर की आकांक्षा को समझा और उसे पूरा किया।

हरदोई एवं उन्नाव

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के हरदोई और उन्नाव में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले अनेक दशकों से हमारा देश, आतंकवाद का कहर झेलता रहा है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो उस दौरान अमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर सजा देगी। आपने देखा है, कुछ दिन पहले ही अमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा भी मिली है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर में भी धमाका किया गया था। वहां के कैट रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया था। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई, तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने का फैसला ले लिया था। ऐसे ही आपको याद होगा, 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को 20 साल की सजा हुई थी। 2007 में लखनऊ, अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक काजमी नाम के आतंकी से मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और उस आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। ■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी, 2022 को पठानकोट, पंजाब में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम नवां पंजाब बनायेंगे जहां चारों ओर खुशहाली होगी।

श्री मोदी ने कहा कि हम पंजाब को पंजाबियत की नज़र से देखते हैं, हमारे विरोधी पंजाब को सियासत के चश्मे से देखते हैं। इसलिए, हमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर के विकास का सौभाग्य मिला। जब भारत विभाजन हुआ, तब कांग्रेस के नेताओं को क्या इतनी भी समझ नहीं आई कि सीमा से 6 किलोमीटर दूर हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि है। वे इस तपोभूमि को भारत में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा न कर के उन्होंने पाप किया है और हमारी भावनाओं को कुचला है। हम सिख दंगों के आरोपियों को सजा दिलवाते हैं। ये उन्हें अपनी पार्टी में बड़े ओहदे देते हैं। यही वो लोग हैं, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। काशी विश्वनाथ धाम बना, तो उस पुण्य काम का भी ये लोग विरोध कर रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर पर सोना चढ़ाने का काम महाराजा रणजीत सिंह जी ने ही किया था। आस्था से उनको चिढ़ है।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें 'पार्टनर-इन-क्राइम' भी मिल गया है। आप देखिए, कितनी समानता है, दोनों दलों में। जब अयोध्या में राम मंदिर बनता है, तो दोनों मिलकर विरोध करते हैं। जब भारत के जांबांज अपना शौर्य दिखाते हैं, तो दूसरी पार्टी के नेता वही बोलते हैं जो पाकिस्तान से बोला जाता है। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में धकेला, दूसरी पार्टी, दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बना रही है। एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। एक ही थाली के चट्टे-बट्टे होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में आमने-सामने होने का दिखावा कर रही हैं जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस अगर ओरिजनल है, दूसरी उसकी फोटोकॉपी है। ■



उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022

भाजपा राष्ट्रवाद, विकासवाद और गरीब-कल्याण के प्रति समर्पित पार्टी है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने वक्तव्य में उत्तर प्रदेश की जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास युक्त, रोजगार युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की यात्रा को जारी रखने के लिए एक बार पुनः भारी बहुमत से भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने का आह्वान किया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के बिसवां (सीतापुर), मछरेहटा (सीतापुर) और भरावन (हरदोई) में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकासवाद और गरीब-कल्याण के प्रति समर्पित पार्टी है। देश में मौजूद छोटी-बड़ी सभी राजनीतिक पार्टियों में से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अखिल भारतीय पार्टी है, बाकी सभी पार्टियां वंशवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद की पार्टी बनकर रह गई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब भाई-बहन की पार्टी बनकर रह गई है। सपा, बसपा और कांग्रेस का मतलब है जाति, धर्म और परिवार के आधार पर राजनीति करना जबकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।

कस्ता, धौरहरा एवं कुर्सी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 14 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के कस्ता (लखीमपुर खीरी), धौरहरा (लखीमपुर खीरी) और कुर्सी (बाराबंकी) में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया।

श्री नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ही दूसरा नाम करप्शन, कमीशन और क्राइम है। सपा हो और अपराधी न हो तो सपा का कार्यकर्ता कैसे होगा! अखिलेश यादव सरकार ने 16,000 करोड़ रुपये

का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया था। ये सर्टिफिकेट देते कैसे क्योंकि इन्होंने तो उसमें भ्रष्टाचार किया था। सपा-बसपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफियाराज को बढ़ावा दिया, गुंडों का आतंक कायम होने दिया जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुंडाराज और माफियाराज का सफाया किया। आज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश को गुंडाराज और माफियाराज की ओर धकेलने वाले लोग इन्हें जेल से ही चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश को फिर दंगों की आग में झुलसायेंगे। सपा के आधे प्रत्याशी जेल में हैं तो आधे बेल पर।

अयोध्या, मिल्कीपुर एवं रुदौली

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मिल्कीपुर और रुदौली में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया।

भगवान् श्रीराम की पावन भूमि और पवित्र सरयू को नमन करते हुए श्री नड्डा ने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद कारसेवकों की शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज आपसे कुछ लोग वोट मांगने आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने रामभक्तों पर गोलियां चलाई थीं। वोट मांगने आने वाले लोगों से आप पूछें कि निर्दोष रामभक्तों पर गोलियां क्यों चलाई थीं? मैं ये बात केवल अयोध्या की जनता से नहीं कह रहा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहा हूँ। कांग्रेस से भी पूछियेगा लेकिन कांग्रेस तो अब पूछने लायक भी नहीं है लेकिन उनसे जरूर पूछियेगा कि

‘हम स्वर्णिम पंजाब के निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं’

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 15 फरवरी 2022 को पंजाब के मौर मंडी, बलुआना और जलालाबाद में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में बनने वाली भाजपा-नीत एनडीए सरकार पंजाब को ड्रग्स, अपराध, माफिया और रेत-माफिया से मुक्त पंजाब बनाएगी। हम स्वर्णिम पंजाब के निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं। नवां पंजाब, भाजपा दे नाल।

श्री नड्डा ने कहा कि सिख-हिंदू एकता एवं भाईचारे के लिए तथा किसानों के कल्याण के लिए पिछले 7 वर्षों में जितना कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है, उतना आजादी के 70 साल में भी किसी ने नहीं किया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिन्होंने लंगर को टैक्स-फ्री किया, श्री श्री हरमंदिर साहिब में चढ़न चढ़ाने हेतु एफसीआरए अप्रूवल दिलाया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण कराया और ब्लैक लिस्ट से सिख नेताओं को बाहर निकाला। आज नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडी के तहत गुरु नानक देव जी से संबंधित रिसर्च कार्य हो रहा है जिसे पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर गुरु गोविंद साहिब के 350वें प्रकाश पर्व को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। जालियांवाला बाग का जीर्णोद्धार कर इसे भव्य रूप प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंहजी के वीर साहिबजादों के त्याग, समर्पण और बलिदान की याद में 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

1984 में हुए सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर बरसते हुए श्री नड्डा ने कहा कि 1984 में सिखों के खिलाफ कांग्रेस की सरकार में नरसंहार हुआ। दोषियों पर कार्रवाई करने के बदले कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। कांग्रेस के नेताओं के हाथ सिख भाइयों के खून से सने हुए हैं। इन्होंने मानवता को शर्मसार किया। इस घटना के 30 साल तक ये गुनाहगार दिल्ली से लेकर पंजाब तक दनदनाते रहे लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। कमीशन पर कमीशन बैठा, जांच पर जांच होती रही लेकिन पीड़ितों के आंसू पोंछने कोई नहीं आया। जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी सरकार आई, तब सिख दंगों के दोषियों पर कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया गया और गुनाहगारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का कार्य किया गया। इतना ही नहीं, दंगों में पीड़ित परिवार को श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। ■

भगवान् श्रीराम जन्मभूमि मामले को कोर्ट में लटकाने और भटकाने का काम क्यों किया था? राम मंदिर को लटकाने और भटकाने वाले आज खुद बीच मझधार में लटक गए हैं, खुद अपनी राह से भटक गए हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण हो रहा है।

सुल्तानपुर और गौरीगंज एवं मुंशीगंज

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर और गौरीगंज एवं मुंशीगंज (अमेठी) में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की विस्तार से चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में लाभार्थियों का हक बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक एकाउंट में पहुंच रहा है। देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कवच मिला है, प्रधानमंत्री आवास के तहत लगभग दो करोड़ गरीबों के घर बने हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 11 करोड़ शौचालय बने हैं, उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 9 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है, घर-घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, लगभग तीन करोड़ घरों में सौभाग्य योजना के तहत बिजली मिली है और जन-धन, आधार एवं मोबाइल के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की सीधी मदद मिल रही है। कोरोना काल में पिछले दो साल से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, कोरोना का मुफ्त टीका लगा है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 15 करोड़ लोगों को दो साल से मुफ्त राशन मिला है और लगभग 42 लाख गरीबों के आवास बने हैं।

श्रावस्ती, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया।

अहमदाबाद बम ब्लास्ट को लेकर अखिलेश यादव को कठघरे में खड़ा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि अभी परसों ही 2008 में हुए अहमदाबाद बम ब्लास्ट के मामले में अदालत का फैसला आया है, जिसमें 38 आतंकियों को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई है। इन बम ब्लास्ट में पकड़ा गया एक आतंकी मोहम्मद सैफ भी है जो आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला है। इस आतंकी का पिता शादाब अहमद समाजवादी पार्टी का नेता है। ये बड़ी विचित्र बात है कि अखिलेश यादव को केवल आतंकवादी परिवार ही मिलता है और कोई नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव का इन लोगों से क्या संबंध है? अखिलेश यादव आज भी आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, आतंकियों की रक्षा कर रहे हैं। ■

पहले करप्शन और कमीशन का खेल चलता था, आज भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम हुई है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 फरवरी, 2022 को मणिपुर के वालपो में किसानों और इम्फाल में बाजार कम्युनिटी के साथ संवाद किया और उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मणिपुर में भारी बहुमत से भाजपा की एन. बीरेन सिंह सरकार बनाने की अपील की।

श्री नड्डा ने गौरवमयी इतिहास और समृद्ध संस्कृति की भूमि मणिपुर की धरती को नमन करते हुए कहा कि याद कीजिये कि पांच साल पहले मणिपुर की क्या स्थिति थी और पांच साल की भाजपा सरकार के बाद आज मणिपुर विकास के रास्ते पर किस तरह आगे बढ़ चला है। पांच साल पहले मणिपुर में ब्लॉकेड, बंद, फेक इमरजेंसी जैसे हालात, फूट डालो राज करो की नीति, एनकाउन्टर, ड्रग्स माफिया का बोलबाला और हर जगह भ्रष्टाचार- यही मणिपुर की पहचान थी। पांच साल पहले ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि मैं मणिपुर की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ शांति से संवाद कर सकूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में श्री एन. बीरेन सिंह सरकार ने मणिपुर की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। आज न कोई ब्लॉकेड है, न बंद। आज मणिपुर में भाजपा की सरकार में सर्वत्र विकास ही शांति और विकास है। कांग्रेस की डिबीजन पॉलिटिक्स ने मणिपुर को बर्बाद करके रख दिया था जबकि भाजपा सरकार में मणिपुर के पिछले पांच साल 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के साल रहे हैं। पहले करप्शन और कमीशन का खेल चलता था, आज भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम हुई है। कांग्रेस की सरकार में मणिपुर में लगभग 6,000 बार बंद हुए थे। हमारी सरकार में एक भी बंद नहीं हुआ। यही कांग्रेस और भाजपा की सरकार में अंतर है। इससे स्पष्ट है कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की एन. बीरेन सिंह की सरकार में पिछले पांच वर्षों में मणिपुर का कृषि बजट 150 करोड़ रुपये से बढ़कर 300 करोड़ रुपये अर्थात् दोगुना हो गया है। जिस मणिपुर की पहचान को खत्म करते हुए कांग्रेस ने इसे बंद और ब्लॉकेड का प्रतीक बनाकर रख दिया था, आज भाजपा की सरकार में मणिपुर को कैटेगरी सी में 2017-18 के लिए सर्वाधिक फल उत्पादन का कृषि कर्मण्य अवार्ड मिला है।



श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक मणिपुर में लगभग 5.82 लाख किसानों को 154 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। पूरे देश में लगभग 23 करोड़ स्वायत्त

हेल्थ कार्ड वितरित किये गए, जबकि मणिपुर में लगभग 2.20 लाख कार्ड दिये गये हैं। मणिपुर में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 1372 स्ट्रक्चर बनाये गये हैं। 2014-15 में मणिपुर में लगभग 345 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती होती थी जबकि आज मणिपुर को ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है। आज मणिपुर के कृषि उत्पादों को जीआई टैग लगाकर दुनिया भर में भेजा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर और पूरे नॉर्थ-ईस्ट को देश के विकास के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। एक नॉर्थ-ईस्ट के तहत केंद्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के मंत्री पिछले 7 वर्षों में 1500 से अधिक बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्रीजी के निर्देश पर हर 15

दिन में केंद्र सरकार के एक न एक मंत्री नॉर्थ-ईस्ट का दौरा कर रहे हैं और हर जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं नॉर्थ ईस्ट में अब तक लगभग 54 बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल के दिनों में मणिपुर में लगभग 5,500 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है।

श्री नड्डा ने कहा हम मणिपुर को बंद प्री, ड्रग्स प्री, ब्लॉकेड प्री और इमरजेंसी प्री प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। ■

याद कीजिये कि पांच साल पहले मणिपुर की क्या स्थिति थी और पांच साल की भाजपा सरकार के बाद आज मणिपुर विकास के रास्ते पर किस तरह आगे बढ़ चला है। पांच साल पहले मणिपुर में ब्लॉकेड, बंद, फेक इमरजेंसी जैसे हालात, फूट डालो राज करो की नीति, एनकाउन्टर, ड्रग्स माफिया का बोलबाला और हर जगह भ्रष्टाचार- यही मणिपुर की पहचान थी

योगी आदित्यनाथ सरकार ने वादों को जमीन पर उतारकर पूरा करने का काम किया है : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा इसी तरह बहाए रखने के लिए एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से भाजपा की डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने की अपील की

मऊरानीपुर, बरुआसागर एवं झांसी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 14 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर, बरुआसागर और क्राफ्ट मेला ग्राउंड, झांसी में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि 2017 के विधान सभा चुनाव के समय हमने बुंदेलखंड की जनता से तीन वादे किये थे। पहला यह कि हम यहां से गुंडों और माफियाओं को खत्म करेंगे, दूसरा यह कि हम बुंदेलखंड में सदियों पुरानी पानी की मांग को पूरा करेंगे और तीसरा यह कि रोजगार के लिए यहां के युवाओं को कोई पलायन नहीं करना पड़ेगा। पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन तीनों वादों को जमीन पर उतार कर पूरा करने का काम किया है।

औरैया एवं मैनपुरी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 15 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के औरैया और मैनपुरी में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथजी ने यूपी से माफियाओं का पलायन करा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में यूपी में डकैती में 72 प्रतिशत, लूट में 62 प्रतिशत, हत्या में 31 प्रतिशत, अपहरण में 29 प्रतिशत और बलात्कार में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है।

शिकोहाबाद, करहल और मोहम्मदी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), करहल (मैनपुरी) और मोहम्मदी (लखीमपुर खीरी) में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि करहल से नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि अब मैं करहल 10 मार्च को आऊंगा। 10 मार्च तो दूर, उन्हें खुद तो करहल में प्रचार करना ही पड़ रहा है लेकिन कड़ी धूप में प्रचार के लिए उन्हें नेताजी को भी उतारना पड़ा है। जब आगाज ही ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? करहल से भी कमल का जीतना तय है।

बांदा, रायबरेली और रायबरेली सदर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 19 फरवरी,



2022 को उत्तर प्रदेश के बांदा, रायबरेली और रायबरेली सदर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। अखिलेश यादव पर बरसते हुए श्री शाह ने कहा कि अखिलेश यादव को यूपी का विकास और कानून-व्यवस्था की बदलती तस्वीर दिखाई नहीं देती है क्योंकि उनकी आंखों पर अभी तक जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण का चश्मा लगा हुआ है।

पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि एक ओर कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जब सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश के संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे। लखनऊ में भी बम धमाके हुए थे। इन हमलों के आरोपियों को छोड़ने का अखिलेशजी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। यह तो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, जिसने हस्तक्षेप करते हुए आतंकवादियों को छोड़वाने से रोका, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाते। बाराबंकी के सिद्धौर में दंगे हो रहा था, तब अखिलेशजी बाराबंकी में गाना सुन रहे थे। आतंकवादी खालिद मुजाहिद और हाकिम तारीक कासमी के खिलाफ जो केस हुए थे उसे अखिलेशजी ने वापस ले लिया था। बाद में हाकिम तारीक कासमी को आजीवन कारावास की सजा हुई। अपने घोषणा पत्र में जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? कांग्रेस और सपा, दोनों पार्टियों ने मिलकर देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उसे निर्बल करने का प्रण लिया है। ■

समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 20 फरवरी, 2022 को प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे नकली समाजवादी हैं। सपा नेता समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद उन्हें छू तक नहीं गया।

श्री सिंह ने कहा कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में तमाम उद्योग बंद हो गए थे, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चिंता की कि देश में कोई भूखा न रहे। आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। सपा ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था बदतर कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे फिर से चुस्त दुरुस्त कर गुंडों के हौसले पस्त किए। अब खुद गुंडे मानते हैं कि बाहर रहने से अच्छा जेल जाना है। सपा-बसपा शासन में बड़े-बड़े माफियाओं के पास आलीशान महल थे। उनकी क्या स्थिति हुई, सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है।

उन्होंने कहा कि पहले उग्र में विमानों की सर्विसिंग व मरम्मत की व्यवस्था नहीं थी, अब जेवर एयरपोर्ट पर यह इंतजाम होगा। इससे उद्योग बढ़ेंगे, होटल खुलेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। कहा कि 2014 के घोषणा पत्र के बिंदुओं को भाजपा ने पूरा किया है।



उन्होंने अपने वक्तव्य में महीने भर में दो बार मिल रहे राशन, हर घर में पानी की उपलब्धता, आयुष्मान भारत के तहत बन रहे कार्ड, कोविड से निपटने के लिए भाजपा सरकार में बनाए गए वैक्सीन और टीके की उपलब्धता पर चर्चा की और फिर से भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया।

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम विकासवादी हैं और समाजवादी पार्टी, बहुजन

समाज पार्टी व कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टियां हैं।

श्री सिंह ने कहा कि जनसंघ का दौर था तब हमने अपने मेनिफेस्टो में लिखा था कि भाजपा सरकार 370 खत्म करके दिखाएगी। हमने इसे खत्म किया। 1984 में हमने कहा था कि भव्य राम मंदिर बनेगा। जो हमने कहा वो किया, अभी जो कह रहे हैं वह आगे भी करेंगे। भाजपा सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकट में देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की। इसके साथ ही साथ लोगों को छत भी मुहैया कराई गई है। सरकार ने जरूरतमंदों को आवास देने के साथ मुफ्त में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया है। भाजपा आंख चुराकर नहीं, आंख में आंख डालकर बात करती है। सदैव से ही भाजपा की कथनी-करनी में कोई अंतर नहीं। हम जो कहते हैं वह करते हैं। ■

अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को मृत्युदंड, 11 को उम्रकैद की सजा

अहमदाबाद (गुजरात) की एक विशेष अदालत ने शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को 18 फरवरी को मौत की सजा सुनायी। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गयी थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे।

अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूपीए) के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनायी। बाकी के 11 दोषियों को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनायी गयी।

न्यायाधीश ए.आर. पटेल ने धमाकों में मारे गए लोगों को एक-एक लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों में से प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये तथा मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अदालत ने 48 दोषियों में से प्रत्येक पर 2.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश पटेल ने हत्या, राजद्रोह और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों और यूपीए तथा विस्फोटक पदार्थ कानून के प्रावधानों के तहत कुल 78 आरोपियों में 49 को आठ फरवरी को दोषी ठहराया था।

गौरतलब है कि शहर में सरकारी सिविल अस्पताल, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित एलजी हॉस्पिटल, बसों में, पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों, कारों तथा अन्य स्थानों पर 26 जुलाई, 2008 को एक के बाद एक धमाके हुए थे जिसमें 58 लोगों की मौत हो गयी थी। ■

परिवार में कम से कम एक रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे



कें द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 8 फरवरी, 2022 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का 'लोक कल्याण संकल्प पत्र' जारी किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्रदेव सिंह, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप-मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा और भाजपा की लोक कल्याण संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष एवं प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित थे। श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार 300 से अधिक सीटों पर जीत के साथ विजय की भव्य कहानी लिखने जा रही है।

'लोक कल्याण संकल्प पत्र' की प्रमुख बातें

समृद्ध कृषि : अगले 5 वर्षों में हम सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। हम 5,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करेंगे। हम 25,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चैन चेम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण करेंगे। हम 5,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करेंगे। साथ ही, स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करेंगे। हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे। हम प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करेंगे। हम प्रदेश में निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत मछुआरों को 1 लाख रुपए तक की नाव 40 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराएंगे।

सशक्त नारी : हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत

वित्तीय सहायता को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए तक करेंगे। हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह हेतु 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली तथा दीपावली पर 2 एल.पी.जी. सिलेंडर मुफ्त प्रदान करेंगे। हम 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करेंगे। हम विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह करेंगे। हम 3 नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और भी सुनिश्चित करेंगे। हम सभी सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाएंगे एवं 3,000 पिक पुलिस बूथ स्थापित करेंगे। हम 5,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ अवंती बाई लोधी स्वयं सहायता समूह (SHG) मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मी बाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगे।

सुगम शिक्षा : हम सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे। हम माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। हम हायर एजुकेशन रेंनोवेशन मिशन शुरू करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय और लखनऊ एवं नोएडा में डिजिटल अध्ययन अकादमी की स्थापना की जायेगी। हम 2,500 करोड़ रुपए की लागत के साथ विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक ब्लॉक में एक आई.टी.आई. की स्थापना करेंगे।

सक्षम युवा : अगले पांच वर्षों में हम हर परिवार में कम से कम

एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। हम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैब्लेट अथवा स्मार्टफोन वितरित करेंगे। हम मेजर ध्यानचंद खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों समेत पूरे प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे।

स्वस्थ प्रदेश : उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने पर हम प्रदेश के हर जिले में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 6 धन्वंतरि मेगा हेल्थ पार्क स्थापित करेंगे। हम 10,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश में हर स्तर पर सुचारु स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे। हम 6,000 डॉक्टरों एवं 10,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र करेंगे। हम 2025 तक उत्तर प्रदेश को टी.बी. मुक्त बनाएंगे।

सुशासन : हम प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। हम लव जिहाद करने पर कम से कम 10 वर्षों की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे।

अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक

विकास : हम उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेंगे। हम अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करके सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण करेंगे। हम बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करेंगे। हम प्रदेश में 5 विश्व स्तरीय एक्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर स्थापित करेंगे। हम सभी एक्सप्रेस-वे के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करेंगे, जिससे 5 लाख युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे। हम आत्मनिर्भर युवा स्टार्ट-अप मिशन बनाकर 10 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हम तीन इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करके 4 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टैक्सटाइल हब बनाकर 5 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 6 औद्योगिक पार्कों के निर्माण को पूरा करेंगे जहां लाखों युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।



आधारभूत संरचना : हम बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों का समग्र विकास करेंगे। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ेंगे। 2024 तक हम 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का रिकॉर्ड समय में निर्माण पूर्ण करेंगे। हम काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज मेट्रो परियोजनाओं पर काम करेंगे।

सबका साथ, सबका विकास : हम हर बेघर को घर उपलब्ध कराएंगे। हम प्रदेश में मां अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था करेंगे। हम प्रदेश में मछुआरा समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति करेंगे।

हम प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना करेंगे, जिनमें ओबीसी युवाओं को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। हम अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों को आवेदन के 15 दिनों के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था करेंगे। हम नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रेप्यूट में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हम संत रविदास मिशन के अंतर्गत प्रदेश

के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (ATS) स्थापित करेंगे। हम वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह करेंगे। हम दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह करेंगे। हम सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा प्रदान करेंगे। हम निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।

सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन : हम महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास का बनारस में, निषादराज गुह का श्रृंगेरपुर में एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करेंगे। हम अयोध्या में श्री राम से संबंधित संस्कृति, शास्त्रों एवं धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय को स्थापित करेंगे। हम सूरदास ब्रजभाषा अकादमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी, केशवदास बुंदेली अकादमी एवं संत कबीर दास भोजपुरी अकादमी की स्थापना करेंगे। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की याद में हम लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी की स्थापना करेंगे। ■

‘सीएम किसान प्रोत्साहन निधि’ की शुरुआत करेंगे



कें द्रीय सड़क परिवर्तन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 9 फरवरी, 2022 को देहरादून में उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र ‘दृष्टि पत्र-2022’ जारी किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मदन कौशिक, प्रदेश भाजपा घोषणापत्र समिति के संयोजक डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के चुनाव प्रभारी श्री प्रह्लाद जोशी और राज्यसभा सदस्य श्री नरेश बंसल उपस्थित थे, जबकि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में वचुंअल तरीके से जुड़े।

‘दृष्टि पत्र-2022’ की प्रमुख बातें

सुरक्षित देवभूमि : भाजपा सरकार ‘हिम प्रहरी योजना’ के अंतर्गत दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

पूर्व सैनिक कल्याण : पूर्व सैनिकों को आसान ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से, भाजपा सरकार ‘जनरल बिपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’ की स्थापना करेगी, इस प्रकार 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 50% की सीमा तक गारंटीकृत कवर प्रदान करेगी।

कृषि : भाजपा सरकार, ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना की तर्ज पर एक ‘सीएम किसान प्रोत्साहन निधि’ की शुरुआत करेगी, जिसके अंतर्गत सभी लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कृषि उपकरण खरीदने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी, जो पीएम किसान सम्मान निधि से प्राप्त 6,000 रुपये के अतिरिक्त होगी। उत्तराखण्ड के प्रत्येक गांव में एक संग्रह केंद्र के साथ प्रत्येक ब्लॉक में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये की कोष निधि का गठन किया जाएगा।

महिला : हम राज्य के सभी गरीब घरों में एक वर्ष में 3 निःशुल्क एल.पी.जी. सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को सहायता राशि देगी।

स्वास्थ्य : उत्तराखण्ड को हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म हब में बदलने के लिए भाजपा सरकार, जहां भी संभव हो, राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी, मेडिकल सीटों की क्षमता में 30 प्रतिशत की वृद्धि करेगी और कुमाऊं में एम्स का एक सैटेलाइट केंद्र स्थापित करेगी।

बुनियादी ढांचा : विशेष रूप से राज्य के 10 पहाड़ी जिलों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए ‘पर्वतमाला परियोजना’ शुरू करेगी।

शिक्षा : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को अंतिम छोर तक बढ़ाने के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत में सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे।

युवा : उत्तराखण्ड में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए, भाजपा सरकार ‘मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना’ प्रारम्भ करेगी जिसके अन्तर्गत इच्छुक बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष तक 3000 रुपये प्रतिमाह तक की राशि प्रदान की जाएगी, जो कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।

पर्यटन : भाजपा सरकार 45 नए हॉटस्पॉट पर फोकस कर राज्य में पर्यटकों की संख्या तिगुनी करेगी। 5 शहरों को मसूरी एवं नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों की तरह उन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी।

निर्धनों का कल्याण : भाजपा सरकार उत्तराखण्ड के असंगठित मजदूरों और गरीबों को 6,000 रुपये तक की पेंशन और 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगी। केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों को नामांकित करने के लिए बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा।

कानून एवं व्यवस्था : भाजपा सरकार लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे कठोर बनाएगी तथा दौषियों के लिए दस साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगी। इस कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों का निस्तारण फ्रास्ट ट्रैक द्वारा किया जायेगा। ■

बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 'मनोहर पर्रिकर कल्याण कोष' बनायेंगे



गोवा को 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 08 फरवरी, 2022 को राजधानी पणजी में प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए गोवा भाजपा का संकल्प पत्र 2022 जारी किया। संकल्प पत्र में हर परिवार को तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने, अगले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर राज्य शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं करने और सरकार बनने के छह महीने के भीतर खनन कार्यों को फिर से शुरू करने का वादा किया गया।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री श्रीपद नाइक, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पार्टी के राज्य चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सदानंद तनावडे उपस्थित थे।

संकल्प पत्र में 'मनोहर पर्रिकर कल्याण कोष' शुरू करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत को 3 करोड़ रुपये तक और प्रत्येक नगरपालिका को 5 करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी। संकल्प पत्र में सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए योग्य परिवारों की महिलाओं को 2 प्रतिशत और पुरुषों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर आवास ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही आवासीय भूखंडों को भी विकसित किया जाएगा।

'संकल्प पत्र-2022' की प्रमुख बातें

गृहणियों का सशक्तिकरण : राज्य में गृहणियों पर बोझ कम करने के लिए गोवा के हर घर में तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाये जायेंगे। डीएसएसवाई के तहत वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।

सभी गोवावासियों के लिए आवास : योग्य परिवारों की महिलाओं को 2 प्रतिशत और पुरुषों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर होम लोन प्रदान कर, अगले पांच वर्षों में सभी गोवावासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और आवासीय भूखंडों को विकसित किया जाएगा।

नागरिकों की सरकार : अगले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर राज्य शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। 'मनोहर पर्रिकर कल्याण कोष' की शुरुआत होगी, जिसके माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

द देने के लिए प्रत्येक पंचायत को 3 करोड़ रुपये तक और प्रत्येक नगरपालिका को 5 करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी।

सभी के लिए जीवन जीने की सुगमता को बढ़ावा दिया

जाएगा : एक 'होमस्टे योजना' शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और होमस्टे उद्योग से जुड़े स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

गोवा का सशक्तिकरण : गोवा के विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्यमियों को प्रति कर्मचारी के लिए 100 प्रतिशत ईपीएफ और ईपीएस सब्सिडी (5,000 रुपये प्रति माह तक) प्रदान की जाएगी और राज्य में रोजगार सृजन के लिए 'रोजगार मेले' आयोजित किये जाएंगे।

स्वर्णिम गोवा : गोवा के खिलाड़ी जो भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतते हैं, उनके लिए 'मिशन गोल्ड कोस्ट' लॉन्च किया जाएगा। गोवा को एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल गंतव्य में बदला जाएगा।

खनन प्रक्रिया फिर से शुरू करना : सत्ता में लौटने के छह महीने के भीतर हम गोवा 'खनिज विकास निगम' के माध्यम से राज्य में खनन फिर से आरंभ किया जाएगा।

गोवा को 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना : हम अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से गोवा को एक ऐसे विकास पथ पर ले जाएंगे, जिसके माध्यम से अगले 10 वर्षों में गोवा को 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

संपूर्ण युवा : हम नए निर्यातनुमुखी एफपीओ को 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके बागवानी उद्योग से जुड़े व्यक्तियों की आय को दोगुना करने का प्रयास करेंगे। हम पूरे गोवा में 20 कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं भी बनाएंगे।

राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना : हम महिला स्वयं सहायता समूहों को किफायती भोजन प्रदान करने के लिए 'अन्नपूर्णा कैटीन' स्थापित करेंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए शॉर्ट-स्टे होम और राज्य भर में दुकानों को एसएचजी द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हर जीटीडीसी होटल में ये विशेष दुकानें होंगी। ■

महिलाओं, युवाओं, किसानों को सशक्त बनाने पर जोर



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 फरवरी, 2022 को मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए इम्फाल, मणिपुर में भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। राज्य के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी, मणिपुर के भाजपा प्रभारी डॉ. संबित पात्रा, चुनाव घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष एवं विदेश राज्य मंत्री डॉ. आर.के. रंजन, महाराजा संजाओबा लीशेम्बा और पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी प्रेस वार्ता में उपस्थित थे।

इम्फाल के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री नड्डा ने कहा कि हम जानते हैं कि मणिपुर सकारात्मक वाइब्स की भूमि है और राज्य ने पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और श्री एन. बीरेन सिंह के गतिशील नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव देखा है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा घोषणापत्र कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी प्रतिबद्धता है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जो बताता है कि हम क्या कहते हैं और कैसे उसे पूरा करते हैं। हम इस घोषणापत्र में किए गए एक-एक वादे को पूरा करेंगे और फिर अगले चुनाव में आपके पास वापस आएंगे।

मुख्य विशेषताएं:

महिला

- ◆ पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को भाजपा सरकार दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इससे महिलाओं और गरीबों का सशक्तिकरण होगा।
- ◆ हम मणिपुर में कॉलेज जाने वाली सभी मेधावी लड़कियों को भी मुफ्त स्कूटी प्रदान करने जा रहे हैं।
- ◆ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को उनकी शिक्षा और विकास के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- ◆ बारहवीं कक्षा पास करने वाले सभी मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करेंगे। यह उच्च शिक्षा के लिए उनका प्रवेश द्वार होगा।

किसान

- ◆ वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये की जाएगी।
- ◆ पीएम किसान के तहत किसानों को वित्तीय सहायता 6,000 रुपये

से बढ़ाकर 8,000 रुपये की जाएगी। मणिपुर भाजपा सरकार अतिरिक्त 2,000 रुपये का भुगतान करेगी।

- ◆ मणिपुर में सभी मछुआरों को 5 लाख रुपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा।
- ◆ मणिपुर की भाजपा सरकार तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

शिक्षा

- ◆ हम मणिपुर के युवाओं के कौशल विकास के लिए मणिपुर कौशल विश्वविद्यालय खोलेंगे।
- ◆ हम मणिपुर में एम्स खोलेंगे।
- ◆ हम आयुष्मान भारत और सीएमएचटी योजनाओं का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेंगे।

पर्यटन और अर्थव्यवस्था

- ◆ पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हम 'एफओ एफओ ट्रेनें' शुरू कर रहे हैं।
- ◆ यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।
- ◆ होमस्टे उद्योग को विकसित करने के लिए ऋण देंगे।
- ◆ लोकतक मेगा ईको-पर्यटन परियोजना का शुभारंभ करेंगे।
- ◆ मणिपुर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भाजपा की मणिपुर सरकार 25 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त कर्ज प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप मणिपुर फंड स्थापित करेगी।
- ◆ हम प्रौद्योगिकी उन्नयन, पूंजी उपलब्धता और बेहतर बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई को ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान करेंगे।

अन्य

- ◆ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर एक 'आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम' शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से इन ब्लॉकों में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रोजगार, कनेक्टिविटी और अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।
- ◆ राज्य में 'एक उपमंडल, एक उत्पाद' कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है।
- ◆ मणिपुर की भाजपा सरकार की सुशासन योजना के तहत हम केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी को सुनिश्चित करेंगे। ■

सरकारी नौकरियों में युवाओं के लिए 75 प्रतिशत और निजी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का संकल्प



भाजपा नीत एनडीए ने 12 फरवरी, 2022 को जालंधर में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इससे पहले एनडीए ने 04 फरवरी, 2022 को चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान 'संकल्प पत्र' नामक 11 प्रस्तावों की सूची भी जारी की थी। एनडीए घोषणापत्र केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा पंजाब चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पीएलसी के श्री रणिंदर सिंह और शिरोमणी अकाली दल (संयुक्त) के श्री तेजिंदर पाल संधू द्वारा जारी किया गया।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गठबंधन ने पंजाब को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाने का संकल्प लिया है।

इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि शांति, सुरक्षा और सद्भाव पंजाब में एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पंजाब को प्रगति और विकास के लिए निवेश की जरूरत है। जब तक शांति और सद्भाव नहीं होगा, कोई भी यहां निवेश करने के लिए आगे नहीं आएगा। उन्होंने परिष्कृत तकनीक का उपयोग करके हथियार और गोला-बारूद और ड्रग्स भेजने के लिए पाकिस्तान द्वारा बार-बार किए जा रहे प्रयासों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बरामद हथियारों और गोला-बारूद का विवरण भी दिया।

घोषणापत्र में पंजाब के हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के पुनरुद्धार के लिए 100 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया। प्रत्येक जिले में नए उद्योगों को उनकी पारंपरिक औद्योगिक विशेषताओं के आधार पर विकसित किया जाएगा। जालंधर, अमृतसर और बठिंडा में 3 नए ड्राई पोर्ट स्थापित करने के साथ साहनेवाल ड्राई पोर्ट की क्षमता को बढ़ाने का वादा किया गया।

संकल्प पत्र में पंजाब के युवाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 75 प्रतिशत और सभी निजी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया गया है। 'सक्षम युवा योजना' के तहत युवाओं को 150 घंटे प्रतिमाह रोजगार की गारंटी दी जाएगी। गठबंधन ने बेरोजगार युवाओं को उनकी डिग्री पूरी होने के बाद दो साल तक 4000 रुपये प्रतिमाह देने का भी वादा किया। सभी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और 300 यूनिट की खपत के बाद तीन रुपये प्रति यूनिट

चार्ज किया जाएगा।

‘घोषणापत्र-2022’ की प्रमुख बातें

किसानों की कर्जमाफी

पांच एकड़ तक की भूमि वाले किसानों के लिए कृषि ऋण माफी के साथ फलों, सब्जियों, दालों और तिलहन के लिए एमएसपी, फसल विविधीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये, सक्षम युवा योजना के तहत हर महीने युवाओं के लिए 150 घंटे काम की गारंटी और बेरोजगार स्नातकों के लिए प्रति माह 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है।

आतंकवाद पीड़ितों के लिए मौद्रिक सहायता

एनडीए ने आतंकवाद के काले दिनों के दौरान आतंकवाद से पीड़ित प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का वादा किया और आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों की शिकायतों के निवारण के लिए आयोग की स्थापना की भी घोषणा की।

300 यूनिट मुफ्त बिजली

एनडीए ने सभी के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और 300 यूनिट के बाद 3 रुपये प्रति यूनिट चार्ज लेने का वादा किया है, जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 4 रुपये प्रति यूनिट और बाकी उद्योग के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क लिया जाएगा।

महिलाओं के लिए आरक्षण

भाजपा ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, सभी जिलों में महिला पुलिस थानों और महिला अदालतों की स्थापना, पोस्ट-मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करने वाली लड़कियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के भत्ता को 10,000 रुपये करने की बात कही है।

वृद्धावस्था पेंशन

राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का भी वादा किया गया है। ■

देश में 2021-22 के दौरान 316.06 मिलियन टन रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ

वर्ष 2021-22 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड 316.06 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में 5.32 मिलियन टन अधिक है

पिछले दिनों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए। इसके अनुसार देश में 316.06 मिलियन टन रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 फरवरी को कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन का लगातार नया रिकार्ड बन रहा है, जो किसान भाइयों-बहनों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का सद्परिणाम है।

दूसरे अग्रिम अनुमान में मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:

- खाद्यान्न – 316.06 मिलियन टन (रिकार्ड)
- चावल – 127.93 मिलियन टन (रिकार्ड)
- गेहूं – 111.32 मिलियन टन (रिकार्ड)
- पोषक/मोटे अनाज – 49.86 मिलियन टन
- मक्का – 32.42 मिलियन टन (रिकार्ड)
- दलहन – 26.96 मिलियन टन (रिकार्ड)
- तूर – 4.00 मिलियन टन
- चना – 13.12 मिलियन टन (रिकार्ड)
- तिलहन – 37.15 मिलियन टन (रिकार्ड)
- मूंगफली – 9.86 मिलियन टन
- सोयाबीन – 13.12 मिलियन टन
- रेपसीड एवं सरसों – 11.46 मिलियन टन (रिकार्ड)
- गन्ना – 414.04 मिलियन टन (रिकार्ड)
- कपास – 34.06 मिलियन गांठें (प्रति 170 कि.ग्रा.)
- पटसन एवं मेस्ता – 9.57 मिलियन गांठें (प्रति 180 कि.ग्रा.)

वर्ष 2021-22 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड 316.06 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में 5.32 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन विगत पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.35 मिलियन टन अधिक है।

2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 127.93 मिलियन टन रिकार्ड अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों के 116.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 11.49 मिलियन टन अधिक है।

वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकार्ड 111.32 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों के 103.88 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 7.44 मिलियन टन अधिक है।

पोषक/मोटे अनाजों का उत्पादन 49.86 मिलियन टन अनुमानित है, जो औसत उत्पादन की तुलना में 3.28 मिलियन टन अधिक है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत पांच वर्षों के 23.82 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक है।

2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन 37.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान 35.95 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1.20 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान तिलहनों का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 4.46 मिलियन टन अधिक है।

वर्ष 2021-22 के दौरान देश में गन्ना का उत्पादन 414.04 मिलियन टन अनुमानित है, जो 373.46 मिलियन टन औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में 40.59 मिलियन टन अधिक है।

कपास का उत्पादन 34.06 मिलियन गांठें (प्रति 170 कि.ग्रा.) अनुमानित है, जो 32.95 मिलियन गांठें औसत उत्पादन की तुलना में 1.12 मिलियन गांठें अधिक है। पटसन व मेस्ता का उत्पादन 9.57 मिलियन गांठें (प्रति 180 कि.ग्रा.) अनुमानित है। ■

कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर 7.5 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हुआ

देश में उपभोक्ताओं को अधिक राहत प्रदान करने तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के दामों में होने वाली बढ़ोत्तरी के कारण घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और वृद्धि को रोकने हेतु भारत सरकार ने 12 फरवरी, 2022 से कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर कृषि उपकर को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। कृषि उपकर में कमी के बाद से कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच आयात कर अंतर बढ़कर 8.25 प्रतिशत हो गया है।

कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच अंतर बढ़ने से घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को रिफाइनिंग के लिए कच्चे तेल का आयात करने में लाभ होगा।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर

भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ने और दोनों देशों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने की संभावना है

गत 18 फरवरी, 2022 को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर और कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों के अपने भविष्य के दृष्टिकोण को ऐसे समय में सामने रखा, जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में 75 साल की आजादी का उत्सव मना रहा है और संयुक्त अरब अमीरात अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है।

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के वाणिज्य एवं उद्योग/वित्त मंत्रियों द्वारा भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (भारत-संयुक्त अरब अमीरात सीईपीए) पर हस्ताक्षर होते देखा। भारत-संयुक्त अरब अमीरात सीईपीए, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संपन्न पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है और यह एमईएनए क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता भी है।

सीईपीए महामारी के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण पहल है और एक प्रमुख व्यापार समझौता है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगा। इससे द्विपक्षीय आर्थिक और निवेश संबंधों में सुधार होगा, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार के रूट खुलेंगे, वैश्विक व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा मिलेगा और कोविड के बाद के विश्व में आर्थिक विकास की गति तेज होगी।

शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि भारत हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है और यह समझौता हमें पहले से कहीं ज्यादा करीब लाता है। आज हमने प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ जो समझौता किया है, वह न केवल एक करीबी मित्र के साथ हमारे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे लिए वैश्विक सहयोग के एक नए चरण का द्वार खोलता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैं आज दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने से खुश हूँ। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस तरह का एक महत्वपूर्ण समझौता 3 महीने से भी कम के रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ है। सामान्यतौर पर ऐसे समझौतों के लिए सालों-साल का समय लगता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता, साझे दृष्टिकोण और विश्वास को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि यह हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक नए युग की शुरुआत करेगा और आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।

गौरतलब है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और ऊर्जा संबंध मजबूत बने हुए हैं। सीईपीए पर हस्ताक्षर लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का प्रमाण है। दोनों पक्ष हरित हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के उपाय, स्टार्ट-अप, स्किलिंग, फिनटेक और हेल्थटेक के नए क्षेत्रों में भी अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और चालू वित्त वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार के 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। भारत गैर-तेल निर्यात के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर संयुक्त अरब अमीरात के कुल गैर-तेल निर्यात का लगभग 14 प्रतिशत साझेदारी करता है।

दरअसल, सीईपीए पांच वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ा सकता है। ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भविष्य के लिए एक साझे दृष्टिकोण का रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है, जिसमें मजबूत, अधिक लचीली अर्थव्यवस्थाओं की परिकल्पना की गई है, जो दोनों देशों के लोगों को स्थायी खुशहाली और कल्याण प्रदान करती है। ■

संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और चालू वित्त वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार के 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। भारत गैर-तेल निर्यात के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर संयुक्त अरब अमीरात के कुल गैर-तेल निर्यात का लगभग 14 प्रतिशत साझेदारी करता है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का हुआ भुगतान

यह योजना सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है, क्योंकि इस योजना में नामांकित लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 4 फरवरी, 2022 तक 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की घोषणा के 6 वर्ष पूरा होने के बाद इस योजना ने आगामी खरीफ 2022 सीजन के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है।



पीएमएफबीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 6 साल पहले शुरू की गई थी, जिसे 2020 में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को आसान बनाने के लिए नया रूप दिया गया था। इसके माध्यम से किसान फसल बीमा ऐप, सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की रिपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। साथ ही, पात्र किसान के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे की धनराशि भी अंतरित की गई।

पीएमएफबीवाई के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)

के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, किसानों के आसान नामांकन के लिए फसल बीमा मोबाइल ऐप, एनसीआईपी के माध्यम से किसान प्रीमियम का प्रेषण, सब्सिडी रिलीज मॉड्यूल और एनसीआईपी के माध्यम से दावा रिलीज मॉड्यूल इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं।

यह योजना सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है, क्योंकि इस योजना में नामांकित लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा

2022-23 के बजट भाषण के दौरान फसल बीमा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में हाल की घोषणा से धरातल पर योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण और भी अधिक मजबूत होगा।

गौरतलब है कि इस योजना के तहत कार्यान्वयन वाले सभी राज्यों में किसानों को 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' के लिए फसल बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए डोर-टू-डोर वितरण अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान पीएमएफबीवाई के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में संपूर्ण जानकारी से अच्छी तरह अवगत हैं। ■

देश में 175 करोड़ से अधिक लगे कोविड-19 रोधी टीके

भाजपा नीत केंद्र की राजग सरकार के ऐतिहासिक प्रयासों व राज्यों के सहयोग से देश में कोविड-19 टीकाकरण का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। देश में कोविड-19 टीकाकरण के नित नए रिकार्ड स्थापित हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत का कुल कोविड टीकाकरण कवरेज 19 फरवरी की सुबह 7 बजे तक 175.03 करोड़ (1,75,03,86,834) के पार पहुंच गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि टीकाकरण के 1,98,09,200 सत्रों के माध्यम से हासिल की गई।

गौरतलब है कि महामारी की शुरुआत के बाद से स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 4,20,37,536 हो गई है। भारत में स्वस्थ होने की दर 98.21 प्रतिशत है।

भारत में वर्तमान सक्रिय मामले 2,53,739 हैं। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.59% हैं। कुल मिलाकर, भारत में अब तक 75.81 करोड़ से अधिक (75,81,27,480) जांच हो चुकी है। एक तरफ जहां देशभर में टेस्टिंग क्षमता बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.50 प्रतिशत है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.80 प्रतिशत दर्ज की गई है। ■

सिद्धांत और नीतियां

पं. दीनदयाल उपाध्याय

जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज

(गतांक से...)

नवीन प्रौद्योगिकी

विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत देश-काल निरपेक्ष होते हुए भी उनका प्रयोग कर उपयुक्त उत्पादन पद्धति का विकास, प्रत्येक देश में उपलब्ध उत्पादन के साधन एवं पण तथा वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थिति सापेक्ष होते हैं। देश की आवश्यकताओं, उपलब्ध प्राकृतिक साधनों, विकसित तथा संभव शक्ति, श्रमिकों को संख्या तथा उनकी शिक्षा, प्रबंध कुशलता और तंत्रपटुता का स्तर एवं संक्रमणशीलता, प्राप्त पूंजी, क्रयशक्ति एवं पण तथा अर्थव्यवस्था के अन्योन्याश्रित अंगों की स्थिति का विचार करके ही हमें उपयुक्त मशीन का निर्धारण एवं निर्माण करना होगा। भारत को पश्चिम की प्रौद्योगिकी का अनुकरण करने के स्थान पर अपने लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का आविष्कार करना चाहिए।

औद्योगिक विकेंद्रीकरण

भारत का औद्योगीकरण प्रमुखतः यंत्रचालित लघु उद्योगों के आधार पर ही होना चाहिए। ये एकात्म मानव के लिए पोषक हैं। विद्यमान आर्थिक कारण उनके पक्ष में हैं। इन उद्योगों के लिए जो कठिनाइयां थीं, वे विज्ञान की आधुनिकतम प्रगति तथा खोजों के बाद दूर हो गई हैं। इनका कृषि के साथ मेल बिठाया जा सकता है। ये गांवों में स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे एक ओर तेजी से होनेवाले नागरीकरण की समस्याओं से बचेंगे तथा दूसरी ओर गांव भी देश की समृद्धि में सहभागी बनेंगे। समाज का शिक्षित एवं युवा यदि गांवों में न रहा तो उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता और न राजनीतिक विकेंद्रीकरण के कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार से तो विकेंद्रीकरण नितांत आवश्यक है।

छोटे उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण बेकारी के निवारण में बहुत सहायक हैं। इनमें पूंजी कम लगती है और इसलिए इनको चलानेवाले साहसियों की संख्या बड़े उद्योगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो सकती है। इस कारण कुल मिलाकर इनके द्वारा अधिक

पूंजीकरण होगा। ये विद्यमान उद्योगों के सहारे विकसित हो सकते हैं। अतः प्रौद्योगिकीय विपूंजीकरण तथा बेकारी को बचा सकते हैं। ये उद्योग श्रमिक की मालिकी के आधार पर चलाए जा सकते हैं। यदि दूसरे श्रमिक मजदूरी पर रखने भी पड़ें तो मालिक और मजदूर परस्पर मानवीय संबंध रखकर सहयोग के आधार पर इनका विकास कर सकते हैं। सहकारिता के लिए भी यहां पर्याप्त गुंजाइश है। ये उद्योग आशुफलदायी हैं, अतः बहुत समय तक पूंजी फंसी नहीं रहती।

बैंक, साख, यातायात तथा राज्य के औद्योगिक नीति संबंधी सभी नियम इस प्रकार बने हैं कि उनमें बड़े उद्योग के साथ पक्षपात होता है। फलतः छोटे उद्योग पनप नहीं पाते। फिर भी पिछले वर्षों में आधुनिक उत्पादन के अनेक क्षेत्रों में छोटे उद्योगों ने इतनी अधिक प्रगति की है कि वे बड़े उद्योगों के साथ टक्कर ले सकते हैं। विदेशी उद्योगों के मुकाबले जैसे स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार बड़े उद्योगों के मुकाबले छोटे उद्योगों को संरक्षण देने की नीति शासन को अपनानी चाहिए।

क्षेत्र विभाजन

छोटे और बड़े उद्योगों में क्षेत्रों का विभाजन होना चाहिए। सामान्यतः उपभोक्ता वस्तुएं छोटे उद्योगों द्वारा तथा उत्पादक एवं मूलभूत वस्तुओं का उत्पादन बड़े उद्योगों द्वारा होना चाहिए।

ग्रामोद्योग

परंपरागत ग्राम और कुटीर उद्योगों में से अधिकांश आज अनार्थिक हो गए हैं। उन्हें आर्थिक बनाना होगा। बिजली और यंत्र के सहारे उनका आधुनिकीकरण करके उन्हें छोटे उद्योगों की श्रेणी में लाना चाहिए। इन उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाए बिना वे टिक नहीं सकते। शैशव में पोषण के लिए संरक्षण उपयोगी है, किंतु वह स्थायी भाव नहीं बनना चाहिए।

ग्रामीण कारीगर

गांव के कारीगरों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्त्वपूर्ण



स्थान है। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण से वे विस्थापित होते जा रहे हैं। नई अर्थव्यवस्था में उनको योग्य स्थान मिल सके, इसका प्रबंध करना होगा।

राष्ट्रीय क्षेत्र

बड़े उद्योग का स्वामित्व विवाद का विषय है। समाजवाद और पूंजीवाद के समर्थक अपने-अपने सिद्धांतों के आधार पर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। भारत की वर्तमान परिस्थिति में, जब विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त क्षेत्र पड़ा हो तथा राज्य एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों की शक्तियां अधूरी सिद्ध हो रही हों, यह विवाद बेमानी है। हमें एक राष्ट्रीय क्षेत्र की कल्पना रखकर प्रत्येक को अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार काम करने का मौका देना चाहिए।

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आवश्यक है। उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोनों क्षेत्रों में सहयोग और पूरकता का भाव रखना चाहिए। सार्वजनिक उद्योगों में 49 प्रतिशत तक पूंजी जनता के अंशदान के लिए खुली रखी जा सकती है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के इस विवाद में जनक्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। वास्तव में तो यही क्षेत्र सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होना चाहिए। हमारी नीति होनी चाहिए कि जनता जहां चाहे वहां, पूंजीपति जहां चाहिए वहां, और सरकार जहां न संभव हो सके वहां।

सार्वजनिक क्षेत्र

अविकसित क्षेत्र में ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं, जहां निजी क्षेत्र या तो प्रवेश की हिम्मत ही नहीं करता अथवा राजनीतिक एवं सामाजिक लक्ष्यों के हित में राज्य को ही उन क्षेत्रों में जाना आवश्यक होता है। निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं—

1. आधारभूत एवं सार्वजनिक सेवा उद्योग इतने पूंजीप्रधान एवं लंबे समय बाद फलदायी हैं कि बिना राज्य के उस क्षेत्र में प्रवेश किए वे स्थापित ही नहीं हो पाएंगे। अतः राज्य को उन उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए।
2. जहां विदेशी पूंजी राजकीय स्तर पर उपलब्ध हो, राज्य को ही उस उद्योग का दायित्व संभालना आवश्यक होगा।
3. निजी क्षेत्र के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करने तथा उसकी पूरकता के लिए भी राज्य को कुछ क्षेत्रों में आना आवश्यक हो सकता है। ये आंशिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र रहेंगे। खाद्यान्न का व्यापार, बैंक, बीमा, यातायात, विदेशी व्यापार इस क्षेत्र में आते हैं।

यदि किसी कारणवश निजी क्षेत्र में चलनेवाले किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता अनुभव हो तो यह प्रश्न एक न्यायिक आयोग को सुपुर्द किया जाए तथा उसकी सिफारिशों के अनुसार ही राष्ट्रीयकरण की दिशा में कदम उठाए जाएं। सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंध स्वायत्त निगमों द्वारा ही होना चाहिए तथा उन पर वे सभी नियम लागू हों, जो निजी क्षेत्र पर लागू होते हैं।

एकाधिपत्य पर रोक

राज्य का कर्तव्य है कि वह आर्थिक कारणों से होनेवाले एकीकरण तथा एकाधिकार को रोके।

पूर्ण रोजगार

प्रत्येक समर्थ और स्वस्थ व्यक्ति के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना आर्थिक नियोजन एवं औद्योगिक नीति का लक्ष्य होना चाहिए। बेकारी को दूर करने के लिए रोजगार के नए अवसरों निर्माण के साथ-साथ अर्ध रोजगार वालों की उत्पादकता एवं आय बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। बढ़ी हुई क्रयशक्ति से वे दूसरों को काम दे सकेंगे। रोजगार संबंधी कार्यक्रमों के निर्धारण, श्रमिकों की संख्या, तज्ञता, उत्पादकता, काम और बेकारी की प्रकृति और व्याप्ति, संक्रमणशीलता आदि सभी प्रश्नों पर विचार करना होगा।

काम न मिलने की अवस्था में जीवनयापन के लिए बेकारी-भत्ते की व्यवस्था होनी चाहिए।

वैज्ञानिकीकरण

अर्धबेकारी को दूर करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकीकरण (Rationalisation) आवश्यक है। किंतु भारत में वैज्ञानिकीकरण मुख्यतः आयात प्रधान होने के कारण सहज नहीं। साथ ही उद्योग के आवश्यक विस्तार के अभाव में कई बार वैज्ञानिकीकरण के कारण छंटे हुए मजदूरों की दूसरी जगह खपत संभव नहीं होती। नई मशीन से अर्थव्यवस्था में तभी गति प्राप्त हो सकती है जब (1) बढ़ी हुई उत्पादकता से प्राप्त आय का श्रमिकों और पूंजी लगानेवालों में वितरण हो; (2) इस आय का कुछ-न-कुछ अंश वित्त संचय तथा उपभोग दोनों के काम आए; (3) देश में पूंजी निर्माण की गति इतनी हो कि नई मशीनों के खरीदने में व्यय करने के बाद भी वह इतनी बची रहे कि केवल छंटीनी किए हुए मजदूरों को ही नहीं, अन्यो को भी काम देने के लिए उद्योग-धंधे प्रारंभ किए जा सकें। सभी पहलुओं पर विचार कर नियोजकों को इस संबंध में कार्यक्रम बनाने चाहिए। ■

(क्रमशः...)

नहीं रहे गायक-संगीतकार बप्पी लाहिड़ी

भारत में 80 और 90 के दशक में सिनेमा में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले गायक-संगीतकार श्री बप्पी लाहिड़ी का 16 फरवरी को मुंबई में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। श्री लाहिड़ी ने 70-80 के दशक में कई फिल्मों के लिए संगीत रचना की, जिन्हें खासी लोकप्रियता मिली। इन फिल्मों में 'चलते-चलते', 'डिस्को डांसर' और 'शराबी' शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री लाहिड़ी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि श्री बप्पी लाहिड़ी का संगीत सबको मोह लेने वाला और विभिन्न भावनाओं की अभिव्यक्ति के सौंदर्य में पिरोया हुआ था। हर पीढ़ी के लोग उनके संगीत से जुड़ जाते थे। उनके हंसमुख स्वभाव की सबको याद आयेगी।



उनके निधन से दुःखी हूँ। उनके परिजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदनाएं।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा कि लोकप्रिय संगीतकार और महान गायक बप्पी लाहिड़ी जी के निधन से गहरा दुःख हुआ। उन्हें उनके उत्कृष्ट गायन के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

श्री लाहिड़ी को 1970 से लेकर 1990 के दौरान भारतीय सिनेमा में 'आय एम ए डिस्को डांसर', 'जिम्मी जिम्मी', 'पग चुंघरू', 'इंतेहा हो गयी', 'तम्मा तम्मा लोगे', 'यार बिना चैन कहां रे', 'आज रपट जाए तो' तथा 'चलते चलते' जैसे गीतों से डिस्को संगीत का दौर शुरू करने का श्रेय दिया जाता है।

उन्होंने 2000 के दशक में 'टैक्सी नंबर 9211' (2006) का 'बम्बई नगरिया' और 'द डर्टी पिक्चर' (2011) के 'उह ला ला' जैसे हिट गीतों को भी अपनी आवाज दी। वह उन गायकों में से एक हैं जिन्होंने 2014 में आयी फिल्म 'गुंडे' का 'तूने मारी एंट्रियां' गीत भी गाया था। उन्होंने बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और गुजराती फिल्मों में भी संगीत दिया। 2014 में श्री लाहिड़ी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी बने। ■

देशभर में चल रहे हैं 966,363 इलेक्ट्रिक वाहन

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर्स/ चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई

देश में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर 2015 से इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (हाइब्रिड एवं) स्कीम (फेम इंडिया) आरंभ की। वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ पहली अप्रैल, 2019 को पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे हैं:

- केंद्र सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए देश में ही एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए 12-05-2021 को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। बैटरी की कीमतों में कमी आने का परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी के रूप में आएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत कवर

किया जाता है जिसे 25,938 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी गई।

- इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर्स/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग के लाइसेंस प्लेट दिए जाएंगे तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों से सड़क कर माफ करने का परामर्श देते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की आरंभिक लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

गौरतलब है कि यह जानकारी 11 फरवरी को राज्य सभा में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई। ■

भारत ने कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। उनका यह भी मानना था कि इसके लिए संकल्प को पूरा करने हेतु हमें सामूहिक भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होगी।

श्री मोदी ने कहा कि दुनिया अभी भी कोविड-19 से जूझ रही है। मानवता ने पिछले सौ वर्षों में इस तरह की कोई चुनौती नहीं देखी है। भारत के लोगों ने वैक्सीन ले ली है और उन्होंने ऐसा न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी किया है। वैश्विक स्तर पर वैक्सीन-विरोधी विभिन्न आंदोलनों के बीच उनका यह व्यवहार सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि लोग महामारी के इस समय में भारत की प्रगति के बारे में सवाल उठाते रहे, लेकिन भारत ने इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह भी सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में घर बनाए जाएं, ये घर पानी के कनेक्शन से लैस हों। इस महामारी के दौरान हमने 5 करोड़ लोगों को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे तर्कसंगत दृष्टिकोण के कारण हमारे किसानों ने महामारी के दौरान फसलों का भरपूर उत्पादन किया। हमने महामारी के दौरान कई बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं को पूरा किया, क्योंकि हमारा मानना है कि वे

(बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं) ऐसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान रोजगार सुनिश्चित करती हैं। इस महामारी के दौरान हमारे युवाओं ने खेलों में काफी प्रगति की है और देश को गौरवान्वित किया है। भारतीय युवाओं ने अपने स्टार्ट-अप के साथ भारत को स्टार्ट-अप के मामले में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल कराया है।

उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान चाहे वह सीओपी26 हो या जी20 से जुड़ा मामला हो या 150 से अधिक देशों में दवा के निर्यात से संबंधित मामला हो, भारत ने नेतृत्व की भूमिका निभाई है और पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमने महामारी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र और कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।

श्री मोदी ने रोजगार संबंधी आंकड़े देते हुए

कहा कि वर्ष 2021 के ईपीएफओ पेरोल के आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 1 करोड़ 20 लाख नए लोगों ने ईपीएफओ पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया है। ये सभी औपचारिक नौकरियां हैं और इनमें से करीब 60 से 65 लाख लोगों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है, यानी यह उनकी पहली नौकरी है।

मुद्रास्फीति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है और जब हम इसकी तुलना अन्य अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आज भारत

एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां मध्यम मुद्रास्फीति के साथ ऊंची वृद्धि दर है।

श्री मोदी ने कहा कि हमें लोगों के लिए काम करना है, चाहे हम किसी भी पक्ष में हों। यह मानसिकता गलत है कि विपक्ष में होने



भारत की प्रगति के बारे में सवाल उठाते रहे, लेकिन भारत ने इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह भी सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में घर बनाए जाएं, ये घर पानी के कनेक्शन से लैस हों

का मतलब लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम नहीं करना है। उन्होंने कहा कि उन्हें तब आश्चर्य हुआ जब कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान कोई बड़ी बात नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी की शुरुआत से ही सरकार ने देश और दुनिया में उपलब्ध हर संसाधन को जुटाने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने सभी को यह भी आश्वासन दिया कि जब तक महामारी मौजूद है, हम देश के गरीबों की रक्षा करेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई भी एक मजबूत और सौहार्दपूर्ण संघीय ढांचे से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न राज्यों के सम्मानित मुख्यमंत्रियों के साथ 23 बैठकें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए विपक्षी दलों के बहिष्कार पर दुःख व्यक्त किया।

‘आयुष्मान भारत योजना’ के अंतर्गत देश में 80 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

श्री मोदी ने कहा कि आज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश में 80 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। ये केंद्र गांव और घर के पास निःशुल्क जांच सहित बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

लोकतंत्र के बारे में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम

लोकतंत्र का सबक उन लोगों से कभी नहीं सीखेंगे, जिन्होंने 1975 में लोकतंत्र को कुचल दिया था। हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी दल हैं। जब कोई परिवार किसी राजनीतिक दल में बहुत अधिक हावी हो जाता है, तो राजनीतिक प्रतिभा को नुकसान होता है।

उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने पूछा— अगर कांग्रेस नहीं होती, तो क्या होता?” प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो आपातकाल नहीं होता, जाति की राजनीति नहीं होती, सिखों का कभी नरसंहार नहीं होता, कश्मीरी पंडितों की समस्याएं नहीं होती।

श्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि हम राष्ट्रीय प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच कोई टकराव नहीं देखते। भारत की प्रगति तब और मजबूत होगी जब देश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जब हमारे राज्य प्रगति करते हैं, तो देश तरक्की करता है।

प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए अपने भाषण का समापन किया कि हमें भेदभाव की परंपरा को समाप्त करना चाहिए और इसी मानसिकता के साथ मिलकर चलना समय की मांग है। एक सुनहरा दौर है और पूरी दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और हमें इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। ■

‘वन ओशन शिखर सम्मेलन’

‘भारत हमेशा से एक समुद्री सभ्यता रही है’

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 फरवरी को ‘वन ओशन शिखर सम्मेलन’ के उच्चस्तरीय सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन के उच्चस्तरीय सत्र को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष ने संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ एवं समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से एक समुद्री सभ्यता रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथ और साहित्य समुद्री जीवन समेत महासागरों के उपहारों का वर्णन करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज हमारी सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है। भारत की ‘भारत-प्रशांत महासागर पहल’ (इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव) में समुद्री संसाधनों को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत, फ्रांसीसी पहल’ राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव-विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन’ (हाई एम्बिशन

कोएलिशन ऑन बायो-डाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन) का समर्थन करता है।

श्री मोदी ने कहा कि हम इस साल अंतरराष्ट्रीय संधि की उम्मीद करते हैं, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। भारत एकल उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया है।

उन्होंने कहा कि तीन लाख युवाओं ने लगभग 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। मैंने अपनी नौसेना को इस साल समुद्र से प्लास्टिक कचरे को साफ करने के लिए 100 जहाज-दिवस का योगदान करने का भी निर्देश दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत को एकल उपयोग प्लास्टिक पर एक वैश्विक पहल शुरू करने के लिए फ्रांस के साथ जुड़ने में खुशी होगी।

उल्लेखनीय है कि ‘वन ओशन शिखर सम्मेलन’ का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9-11 फरवरी के दौरान किया गया। ■

मोदी सरकार में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया : डॉ. भारतीबेन शियाल

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद डॉ. भारतीबेन शियाल से नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर कमल संदेश के सह संपादक **संजीव कुमार सिन्हा** और कमल संदेश डिजिटल टीम के सदस्य **विपुल शर्मा** ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, महिला कार्यकर्ता को लेकर भाजपा का संगठनात्मक दृष्टिकोण एवं महिला सशक्तिकरण हेतु मोदी सरकार के असाधारण प्रयासों को लेकर चर्चा की। प्रस्तुत है इस बातचीत के प्रमुख अंश:



सबसे पहले हमें यह बताइए कि आप भाजपा से कब और कैसे जुड़ीं? अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताएं।

देखा जाए तो मेरी राजनीतिक यात्रा वर्ष 2000 में शुरू हुई। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और अच्छे वोटों से जीती। यह वह दौर था, जब जिला पंचायत पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते भाजपा को जिला पंचायत पर शासन करने का अवसर मिला और मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। इसके बाद भाजपा संगठन के साथ जुड़कर भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। जिला स्तर पर मुझे तीन बार उपाध्यक्ष पद पर कार्य करने का मौका मिला। इसके अलावा मंडलों और बहुत सारे प्रकोष्ठों की प्रभारी रही। इसके उपरांत प्रदेश स्तर पर ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में रहने का अवसर मिला। ऐसे ही प्रदेश कार्यकारिणी में भी रहने का अवसर मिला। इसके बाद वर्ष 2012 में तलाजा विधानसभा से चुनाव लड़ी और अच्छे अंतर से जीत हासिल की। वर्ष 2014 में मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला और यह पहली बार था जब किसी महिला को भावनगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया था। जब चुनाव परिणाम आए तो पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में मेरी जीत का अंतर सबसे अधिक था। ऐसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे एक बार फिर भावनगर से चुनाव लड़ने का अवसर मिला और इस बार मेरी जीत का अंतर पिछली बार की तुलना में और बेहतर हो गया। संगठन स्तर पर भी मेरा निरंतर योगदान रहा। इसके बाद मुझे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया।

भाजपा संगठन में महिला भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं?

स्थापना काल से ही भाजपा में महिलाओं को उचित स्थान मिलता आया है। संगठनात्मक स्तर पर कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं

की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। मेरे अनुभव में पार्टी के भीतर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित होती है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर पांच उपाध्यक्ष, एक महामंत्री एवं चार मंत्री महिला कार्यकर्ता हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर महिला मोर्चा है, जिनके माध्यम से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

संगठन में महिला कार्यकर्ताओं के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?

हमारी पार्टी में मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। देखा जाए तो जब किसी महिला को संगठन में कोई दायित्व मिलता है या वह जनप्रतिनिधि बनती है, तो उन सभी को पार्टी प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। जब मैं विधानसभा में चुनकर पहुंची थी, तो उस दौरान भी हमारे लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया था। जिसमें हमें बताया गया कि कैसे विधानसभा में कार्य करना है और कैसे आम जनता के लिए कार्य करना है। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से अधिकारियों के साथ काम करना है और किस प्रकार सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना है, यह भी बताया गया।

मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

मैं लंबे समय से श्री नरेन्द्र मोदी के साथ काम कर रही हूँ। वह जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो मैं विधायक थी। गुजरात और केंद्र की मोदी सरकार में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चिंता की गई है। सालों से देखा गया है कि भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसे में यदि

इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा चिंता किसी ने की है तो वह मोदी सरकार ने की है। देश में सबसे मोदी सरकार आई है तबसे महिलाओं के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। मोदी सरकार ने देश भर में महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया और उनको उचित सम्मान दिया। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए। ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना है, मुद्रा योजना है, जिसके तहत कर्ज लेनेवाले में से 76 प्रतिशत महिलाएं हैं। मोदी सरकार की 'मातृत्व योजना' के तहत बच्चे के जन्म के समय महिलाओं के खाते में 6000 रुपए जमा किए जाते हैं, जिससे महिला अपनी और अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है। इसके अतिरिक्त मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

देश की ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूहों को मजबूती दी जा रही है। इसके अलावा तीन तलाक की कुप्रथा को मोदी सरकार ने समाप्त किया है। वहीं महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों में सुधार कर उनको सख्त बनाया गया है। यह मोदी सरकार के प्रयास ही हैं जिनके कारण हरियाणा से आरंभ हुए 'बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ अभियान' का असर अब पूरे देश में दिखने लगा है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

देखिए, दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। परिणामस्वरूप, राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी अपेक्षित है, जैसा अन्य किसी भी क्षेत्र में होता है। हाल के दिनों में भारत में इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। संगठन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ भाजपा ने सरकार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया है। मोदी सरकार में वर्तमान में 11 महिला मंत्री हैं। इसी तरह, पिछली सरकार में लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन और विदेश मंत्री के पद पर लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज थीं।

भारतीय संस्कृति में महिलाओं का क्या स्थान है?

भारतीय संस्कृति में वेद, उपनिषद और शास्त्रों में महिलाओं को हमेशा देवी का दर्जा दिया गया है और उनको पूजनीया माना गया है- 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' या 'नारी तू नारायणी'। हां, मैं यह मानती हूँ कि बीच में एक कालखंड ऐसा आया जब इस धारणा में कुछ बदलाव हुआ और महिलाओं का शोषण आरंभ हुआ, महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी देने से इंकार किया गया।

लेकिन सबसे मोदी सरकार आई है, तबसे महिलाओं को लेकर धारणा में बदलाव आया है। उनकी सुरक्षा, स्वरोजगार और आत्मसम्मान को सुनिश्चित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर,

मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, जहां सिर्फ महिला कुली कार्यरत हैं। ऐसे ही देखें तो आज रिक्शा ड्राइवर से लेकर फाइटर प्लेन भी महिलाएं चला रही हैं। खेलकूद में महिलाओं ने देश का नाम ऊंचा किया है। राजनीति में भी महिलाएं आगे आ रही हैं और कहा जा सकता है कि स्थिति में बहुत सुधार हो रहा है।

गुजरात में जब श्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक योजनाएं प्रारंभ की थी। देश भर में इसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। कृपया इस संबंध में हमें बताएं।

मोदीजी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सबसे अधिक महिलाओं की चिंता की। मुख्यमंत्री रहते हुए श्री मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते थे, तो उन्हें विभिन्न उपहार मिला करते थे, जिनको परंपरागत तौर पर तोशाखाना में जमा करवा दिया जाता था, लेकिन माननीय मोदीजी इस संदर्भ में एक प्रस्ताव लेकर आए और उनके कहने पर इन उपहारों की नीलामी प्रक्रिया को आरंभ किया गया और इस प्राप्त राशि से महिलाओं के लिए 'कन्या केलवणी निधि' बनाया गया। इसके माध्यम से बेटियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए। गुजरात में जिन स्थानों पर बेटियों में अशिक्षा और ड्रॉपआउट दर अधिक थी, वहां 'कन्या केलवणी रथ' के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया गया।

इसके अतिरिक्त गुजरात में बेटियों के लिए फ्री एसटी पास, मुफ्त साइकिल, यूनिफॉर्म, पुस्तकें और विभिन्न स्कॉलरशिप कार्यक्रमों को चलाया गया। गुजरात सरकार विद्यालक्ष्मी बॉन्ड भी लेकर आई। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी महिलाएं पशुपालन उद्योग से जुड़ी हुई हैं और हर गांव में एक दूध उत्पादक मंडली है। इनमें से जिन दूध उत्पादक मंडली में केवल महिला सदस्य हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। ऐसे ही प्रॉपर्टी लेनेवाली महिलाओं को स्टॉप ड्यूटी से छूट दी गई थी। सरकारी भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है। स्थानिक स्वराज की संस्थाओं— ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका और महानगरपालिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। गुजरात में नारी अदालत की शुरुआत मोदीजी ने की, महिला सुरक्षा के लिए गुजरात में 181 नंबर हेल्पलाइन है। गुजरात में महिला पुलिस स्टेशनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। वहीं, प्रदेश में 'सुरक्षा सेतु' योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुजरात सरकार 'व्हालीदिकरी' योजना भी चला रही है, जिस घर में बेटी होती है, गांव के सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी बैंड-बाजे लेकर उनके घर जाते हैं और उनके खाते में एक हजार रुपए जमा कर दिया जाता है। ऐसे ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया। ■

उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक यात्रा: एक नजर (भाग 3)



राम प्रसाद त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश ने जनसंघ और भाजपा की राजनीतिक यात्रा को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 में अपनी शुरुआत से लेकर वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत तक, उत्तर प्रदेश में भाजपा का उदय अभूतपूर्व रहा है। उत्तर प्रदेश में जब भी भाजपा की सरकार बनी, चाहे 1990 के दशक में श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व वाली या 21वीं सदी की शुरुआत के बाद श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली या मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार, सभी भाजपा सरकारों ने कानून का शासन स्थापित किया है; तेजी से विकास सुनिश्चित किया है, बड़े सुधार किये हैं और नागरिकों के कल्याण के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश में लोक कल्याणकारी नीतियों और बेहतर शासन व्यवस्था ने भाजपा को एक अलग राजनीतिक ताकत बना दिया है। इसी के साथ भाजपा राज्य और अन्य प्रांतों के लोगों का दिल भी जीतने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारों के 'राष्ट्र प्रथम और स्वयं अंतिम' वाले आदर्श वाक्य को लगातार नागरिकों का अटूट समर्थन मिलता रहा है।

श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली बार जून, 1991 से दिसंबर, 1992 तक और दूसरी बार सितंबर, 1997 से फरवरी, 1998 तक भाजपा सरकार के उदय ने सुशासन और कल्याणकारी उपायों को लेकर आम धारणा को बदलने का काम किया। श्री कल्याण सिंह ने प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने का प्रयास किया और वह राज्य में वर्तमान भाजपा सरकार की प्रेरणा रहे, जिन्होंने समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग को सशक्त बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी हद तक पुनर्परिभाषित किया। उन्होंने ओबीसी और अनुसूचित जाति के अंदर मौजूद अति पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में युक्तिसंगत आरक्षण देने का प्रयास किया, ताकि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंच सके।

श्री राम प्रकाश गुप्ता कुछ समय के लिए 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर, 2000 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक सुधार और राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये।

वर्ष 2000 में श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने भी राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। विज्ञान विषयों का आधुनिकीकरण और वैदिक गणित

को पाठ्यक्रम में शामिल करना उनकी कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां थीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में अमिट योगदान दिया है।

इसके विपरीत कांग्रेस, सपा और बसपा शासन के दौरान उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य में बदल गया, जो भ्रष्टाचार, अराजकता, अपराध, भाई-भतीजावाद, गुंडागर्दी और आतंकवाद के लिए बदनाम था। कनेक्टिविटी की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राजधानी लखनऊ तक पहुंचना भी काफी मुश्किल काम था तथा विकास कुछ मुख्यमंत्रियों के पैतृक इलाकों तक ही सीमित था। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार में राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी और राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अपराधिक घटनाएं, सांप्रदायिक उन्माद और विकास की सुस्त चाल ने लोगों को परेशान कर दिया था।

2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बहुआयामी विकास का बीड़ा उठाया और इतिहास रच दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और राज्य में सुशासन स्थापित किया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पूरे पांच साल शासन किया। योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रति लोगों की धारणा बदलने में सफल रहे हैं और इसे विकास, विश्वास और सुशासन के पथ पर आगे ले गये। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे इस अंधविश्वास को भी तोड़ा, जिसके तहत सभी मुख्यमंत्री आर्थिक केंद्र नोएडा का दौरा करने में कतराते थे, योगी आदित्यनाथ ने कई बार नोएडा का दौरा किया और राज्य की विकास यात्रा को गति देने के लिए यहां सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का मार्ग प्रशस्त किया। अब भाजपा के सुरक्षित शासन में उत्तर प्रदेश निवेश के विभिन्न अवसरों को आकर्षित कर रहा है। इससे पहले राज्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की राष्ट्रीय रैंकिंग में 14वें स्थान पर था, लेकिन अब यह दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य ने पिछले 56 महीनों में 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किया है और निर्यात के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है।

भाजपा सरकार ने आम लोगों, महिलाओं और कारोबारियों के लिए सुरक्षा का माहौल बनाया है। राज्य प्रशासन ने अपराधियों की 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है और अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। राज्य प्रशासन अब कानून के दायरे में रहते हुए

अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपट रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई में जाति और धर्म को ढाल नहीं बनाया जाता है। भाजपा सरकार के शासन में पिछले पांच सालों में आतंकवादी वारदातें, दंगे और माफियाओं की अवैध कार्रवाई बीते दिनों की बात हो गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य जिसे पहले देश के विकास में एक रोड़ा माना जाता था, ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनौतियों को अवसरों में बदला है और अब भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रणी बन गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर 42 लाख लोगों को घर दिए। राज्य ने डीबीटी योजना के तहत नागरिकों के अकाउंट में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण किया है। साथ ही, पिछले 56 महीनों में राज्य के लगभग 4.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिला है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार सुशासन का एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है। सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए कई अभियान चलाए हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि “अपराधी या तो अपना रास्ता बदल लें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें” और इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारियों और मुठभेड़ों को अंजाम दिया। नवंबर, 2021 में जारी एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 37,000 गिरफ्तारियां की गईं। इनमें से 11,000 कुख्यात अपराधी थे। अवैध बूचड़खानों को बंद करने से लेकर महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दस्ता बनाने तक, सभी कदम यूपी की कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

देखा जाए तो अतीत में कुछ दलों ने किसानों का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास तो किया, लेकिन किसी भी दल ने किसानों की बुनियादी समस्याओं जैसे- बिजली की उपलब्धता, पानी की आपूर्ति, बाजार से जुड़ाव, सरकारी खरीद और उनके बकाया का समय पर भुगतान करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया। भाजपा सरकार ने लंबे समय से चली आ रही किसानों की इन समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए। योगी सरकार ने ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के तहत किसानों के बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।

भाजपा के सुरक्षित शासन में उत्तर प्रदेश निवेश के विभिन्न अवसरों को आकर्षित कर रहा है। इससे पहले राज्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की राष्ट्रीय रैंकिंग में 14वें स्थान पर था, लेकिन अब यह दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य ने पिछले 56 महीनों में 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किया है और निर्यात के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है

इसी तरह एमएसपी, लाभकारी मूल्य और चीनी मिलों को पुनर्जीवित करके भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों के लिए अभूतपूर्व काम किया। गरीब, पिछड़े वर्ग और दलितों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीतियां बनायीं, जिनका असर अब दिखने लगा है।

महिलाओं को खुले में शौच के अपमान से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा सरकार ने ‘स्वच्छ भारत योजना’ के तहत राज्य में दो करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है। ऐसे ही पीएम आवास योजना के तहत 34 लाख से अधिक पक्के घर बनाए हैं और गरीब लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी दिए हैं।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। बारहमासी पानी की समस्या को हल करने से लेकर डिफेंस कॉरिडोर और मजबूत सड़क नेटवर्क जैसे कई कदम उठाये गये, सरकार पलायन को रोकने और इस क्षेत्र को रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेज गति से शुरू किया जा चुका है। ये बुनियादी ढांचे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगे और एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में मदद करेंगे।

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को भी कोरोना महामारी के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना मिली है। केरल जैसे छोटे राज्यों की तुलना में राज्य में मृत्यु दर बेहद कम रही। राज्य ने तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कोई भी गरीब ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन से वंचित रहकर भूख न सोए। महामारी के दौरान श्रमिकों तथा छात्रों की आवाजाही और भोजन वितरण के सुचारू प्रबंधन को सुनिश्चित किया गया। योगी सरकार के अनुकरणीय कार्य ने देश में उत्तर प्रदेश को लेकर बनीं नकारात्मक धारणा को बदलने का काम किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सुचारू कार्यान्वयन कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या निर्मल गंगा अभियान तक योगी सरकार के कार्य स्वयं इसकी सफलता की कहानी बयान करते हैं। यह वही राज्य है जहां पहले दंगों का चलन था, लेकिन पिछले पांच वर्षों में राज्य सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त रहा, जो पार्टियों के संस्थापकों के सपनों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश ने पिछले पांच वर्षों में लगभग सभी मोर्चों पर शानदार सफलता हासिल की है और विधानसभा चुनावों के बीच राज्य में भाजपा को समाज के सभी वर्गों का भारी समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। ■ (समाप्त)

'मुद्रा योजना' महिला नेतृत्व वाले विकास की गाथा लिखने में सहायक सिद्ध हो रही है



विकास आनन्द

मो दी सरकार के सत्ता में आने के बाद महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इस दौरान सरकार ने 'महिलाओं के विकास' के पारंपरिक अर्थ को बदलने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'महिलाओं के विकास' के स्थान पर अब 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' पर जोर दिया है। देश की यह आधी आबादी हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखती है। इसी को देखते हुए केंद्र की भाजपा सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं और पहल की हैं। ऐसे ही एक पहल है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), जो महिला उद्यमियों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। हालांकि, यह योजना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है।



सरकार के एनएसएसओ सर्वेक्षण (2013) के अनुसार देश में 5.77 करोड़ छोटी/सूक्ष्म इकाइयां हैं, जिनमें लगभग 12 करोड़ लोग कार्यरत हैं और इसमें से अधिकांश एकल स्वामित्व वाले उद्यम हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के पास इनमें से 60 प्रतिशत इकाइयों का मालिकाना हक है और ज्यादातर इकाइयां औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर हैं। इन इकाइयों के पास कर्ज लेने के लिए अनौपचारिक स्रोत नहीं है और उनको अपने व्यापार के लिए ज्यादातर निजी पूंजी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस क्षेत्र में वित्तपोषण की मांग को देखते हुए 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) की स्थापना 'अनफंडेड' सूक्ष्म कंपनियों को निधि देने के लिए की गई थी। योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यम को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जो उद्यमियों की विभिन्न आवश्यकताओं के हिसाब से होता है। मुद्रा, पीएमएमवाई के अंतर्गत तीन श्रेणियों में— 'शिशु', 'किशोर', और 'तरुण' में ऋण देती है। 'शिशु' योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, 'किशोर' योजना में 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक और 'तरुण' योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

इस योजना का प्रमुख लक्ष्य भारत में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। 'मुद्रा ऋण' बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उन महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है जो अपना उद्यम शुरू करने की इच्छा रखती हैं। मुद्रा ऋण पुरुषों और महिलाओं के लिए उपलब्ध है, जो अपने छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को शुरू करने, विस्तार करने, समर्थन करने या आधुनिकीकरण करने की इच्छा रखते हैं। महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने में यह योजना फायदेमंद साबित हो रही है। महिला व्यवसायियों के लिए अब तक 70 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मुद्रा योजना के तहत रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रा योजना ने लगभग 3 वर्षों (यानी 2015 से 2018 तक) की अवधि के दौरान 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद की। समग्र स्तर पर मुद्रा लाभार्थियों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त रोजगार में शिशु श्रेणी के ऋण का लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा है, जिसके बाद क्रमशः किशोर (19 प्रतिशत) और तरुण (15 प्रतिशत) श्रेणियां हैं। 26 नवंबर, 2021 तक इन ऋणों के कुल लाभार्थियों की संख्या 32.11 करोड़ थी। इन 32.11 करोड़ लोगों में से 21.74 करोड़ महिलाएं थीं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्यक्ष रूप से सृजित सभी रोजगारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत है। ■

‘जल जीवन मिशन’ के तहत नौ करोड़ ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा

पिछले 30 महीनों में 5.77 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया गया।
98 जिले, 1,129 प्रखंड, 66,067 ग्राम पंचायतें और 1,36,135 गांव ‘हर घर जल’ के दायरे में आ चुके हैं

वर्ष 2024 तक देश के हर घर तक नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के लिए ढाई साल से भी कम अवधि तथा कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की दिक्कतों के बावजूद जल जीवन मिशन ने 5.77 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल उपलब्ध करा दिया है। परिणामस्वरूप आज देश के नौ करोड़ ग्रामीण घरों को नल से साफ पानी की आपूर्ति का सुख मिल रहा है।

15 अगस्त, 2019 को मिशन की घोषणा होने के वक्त भारत में 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में ही पानी का कनेक्शन था। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की प्रधानमंत्री की परिकल्पना सम्बंधी सिद्धांत के तहत छोटी सी अवधि में ही 98 जिले, 1,129 प्रखंड, 66,067 ग्राम पंचायतें और 1,36,135 गांव ‘हर घर जल’ के दायरे में आ चुके हैं।

गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुदुच्चेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में हर ग्रामीण घर में नल से जलापूर्ति हो रही है। पंजाब (99 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (92.4 प्रतिशत), गुजरात (92 प्रतिशत) और बिहार (90 प्रतिशत) जैसे कई अन्य राज्य भी 2022 में ‘हर घर जल’ के मुहाने पर पहुंच गये हैं।

पांच वर्षों की अवधि में हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने के इस भगीरथी कार्य को पूरा करने के लिये 3.60 लाख करोड़ रुपये

की धनराशि आवंटित की गई। केंद्रीय बजट 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिये ‘हर घर जल’ को 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2021-22 में राज्यों को 26,940 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों को जल तथा स्वच्छता सम्बंधी अनुदान दिये जाने की 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से जुड़ा है। अगले पांच वर्षों यानी 2025-26 तक के लिये 1,42,084 करोड़ रुपये के आश्वस्त वित्तपोषण का प्रावधान है। देश के ग्रामीण इलाकों में होने वाले इस भारी निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तथा आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। साथ ही गांवों में रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं।

पूर्व के जलापूर्ति कार्यक्रमों से हटकर ‘जल जीवन मिशन’ का पूरा ध्यान जल सेवा आपूर्ति पर भी है, न सिर्फ जलापूर्ति अवसंरचना के निर्माण तक। जल जीवन मिशन का मूलमंत्र है ‘कोई पीछे न छूट जाये,’ और इस तरह वह सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर ‘हर घर को नल से जल’ की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।

सदियों से घरों के लिये पानी ढोकर लाने के कठिन श्रम से माताओं और बहनों को मुक्ति दिलाने तथा उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिये जल जीवन मिशन का प्रयास है। मिशन ग्रामीण परिवारों के लिये जीवन को सुगम बना रहा है तथा उन्हें गौरव और सम्मान के साथ जीने का अवसर दे रहा है। ■

पीएसएलवी सी52 मिशन का सफल प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 14 फरवरी को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब इसने पीएसएलवी सी52 प्रक्षेपण यान (रॉकेट) से 1710 किग्रा के भू-प्रेक्षण उपग्रह ईओएस-4 और दो छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएसएलवी सी52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी। एक ट्वीट

में प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएसएलवी सी52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई। ईओएस-4 उपग्रह से कृषि, वानिकी और बागान, मिट्टी में नमी और जल विज्ञान सहित बाढ़ के जोखिम वाले स्थानों का मानचित्र बनाने में सभी मौसमी परिस्थितियों में प्रासंगिक हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्राप्त होंगी।

उल्लेखनीय है कि ईओएस-4 एक रेडार प्रतिबिंबन उपग्रह है, जिसे कृषि, वानिकी एवं



पौधारोपण, मृदा नमी एवं जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता प्रतिबिंबों को उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। ■

‘कर्मनिष्ठ दिल्ली नगर निगम’ रिपोर्ट का लोकार्पण

लोक नीति शोध केंद्र (पीपीआरसी), नई दिल्ली ने 22 फरवरी, 2022 को दिल्ली के नगर निगमों की उपलब्धियों पर 'कर्मनिष्ठ दिल्ली नगर निगम' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर आईसीसीआर (विदेश मंत्रालय) के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, विदेश राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत कुमार गौतम, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली के सांसद, पीपीआरसी के निदेशक डॉ. सुमीत भसीन, समिति के सदस्य और कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस शोध रिपोर्ट का लोकार्पण करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी की प्रभावशीलता को क्षीण करने



के उद्देश्य से धन हस्तांतरित करने में देरी की जाती है। फिर भी एमसीडी ने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का हर संभव प्रयास किया है। काफी वर्षों से से लंबित रानी झांसी फ्लाईओवर का कार्य पूरा किया गया। साथ ही, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एमसीडी द्वारा प्रभावी ढंग से काम

किया गया है। किसी भी महामारी और चिकित्सा आपात स्थिति के लिए राजधानी को तैयार करने के लिए एमसीडी द्वारा चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली एमसीडी कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ कर्मनिष्ठ भी है। डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि पीपीआरसी ने शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखकर घोषणापत्र की समीक्षा से लेकर विभिन्न मुद्दों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए विभिन्न अध्ययन किए हैं। ■



कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान! सदस्यता प्रपत्र



नाम :

पूरा पता :

पिन :

दूरभाष : मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल :

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	<input type="checkbox"/>	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	<input type="checkbox"/>
	तीन वर्ष	₹1000/-	<input type="checkbox"/>	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	<input type="checkbox"/>

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. : दिनांक : बैंक :

नोट : डीडी / चेक 'कमल संदेश' के नाम देय होगा।

मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

**कमल
संदेश**

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकजी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका



नई दिल्ली में अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास पर मिलते अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी



गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली स्थित करोलबाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पूजा-अर्चना करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



नई दिल्ली में भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर में विभिन्न 100 स्थानों पर सक्रिय किसान ड्रोन का अवलोकन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



नई दिल्ली में शिक्षा और कौशल क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एच.ओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"

36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23

Licence to Post without Prepayment

Licence No. U(S)-41/2021-23

खुशहाल किसान
समृद्ध राष्ट्र



खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत जारी है किसानों से MSP पर धान की खरीद

- MSP पर धान की खरीद 606.19 लाख मीट्रिक टन
- लाभान्वित किसान 77 लाख से अधिक
- MSP पर किसानों को भुगतान 1,18,812.56 करोड़ रुपये

MSP: न्यूनतम समर्पण मूल्य
23 जनवरी, 2022 तक*
पूरा पढ़ें - bitly.ws/o684



प्रधानमंत्री जन धन योजना
विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना



- कुल जन धन खाते 44.44 करोड़
- महिला खाताधारक 24.72 करोड़ (कुल लाभार्थियों के 55% से अधिक)
- ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की बैंक शाखाओं में खुले खाते 29.68 करोड़ (कुल खातों के 66% से अधिक)
- खातों में जमा कुल धनराशि 1.57 लाख करोड़ रुपये

जन धन खाते बन रहे हैं गरीबों की आर्थिक प्रगति की कुंजी

23 जनवरी, 2022 तक*
गति - amjyog.gov.in

स्वस्थ भारत - सशक्त भारत

भारतीय जन औषधि परियोजना

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना बन रही है स्वस्थ भारत की संजीवनी

- देशभर में क्रियाशील जन औषधि केंद्र 8,664
- केंद्रों पर 1,451 दवाइयां और 240 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध
- केंद्रों से दवाईं तुरंत पर उपभोक्तकों को 50% से 90% तक की बचत



23 जनवरी, 2022 तक* स्रोत - janoushadhi.gov.in

राष्ट्रीय बालिका दिवस
बेटियों को शिक्षित, सुरक्षित और समृद्ध बना रही है मोदी सरकार



- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुले खाते - 2.26 करोड़ से अधिक
- खातों में जमा धनराशि - 80,500 करोड़ रुपये से अधिक
- 2015 के बाद से 10 वर्ष से अधिक उम्र की स्कुली शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों की संख्या में हुई 15% की वृद्धि

1,000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में हुई वृद्धि

991 (2015-16) vs 1,020 (2020-21)

स्रोत: भारत सरकार



छायाकार: अजय कुमार सिंह